● वर्ष : 17 ● अंक : 206 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

रविवार 17 मई 2026

ऊर्जा संकट से दुनिया की उपलब्धियां खतरे में, भारत बनेगा वैश्विक विकास इंजन : प्रधानमंत्री

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट, लोकतंत्र, सेमीकंडक्टर और भारत की वैश्विक भूमिका पर रखे विचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को हेग में वैश्विक ऊर्जा संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि दुनिया ने समय रहते इस चुनौती का समाधान नहीं किया, तो पिछले कई दशकों में हासिल की गई विकास संबंधी उपलब्धियां नष्ट हो सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया की बड़ी आबादी एक बार फिर गरीबी के जाल में फंस सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी पांच देशों की छह दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंचे हैं। यहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया लचीली और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की आवश्यकता महसूस कर रही है। भारत और नीदरलैंड मिलकर पारदर्शी एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद नीदरलैंड यूरोप का प्रमुख प्रवेश द्वार बन सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्य भूमि यूरोप में भारतीय

मूल के लोगों का सबसे बड़ा समुदाय नीदरलैंड में निवास करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए कहा, "जिस प्रकार भारत कमल के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नीदरलैंड ट्यूलिप के लिए प्रसिद्ध है। ट्यूलिप और कमल दोनों यह सिखाते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हों या मिट्टी में, सौंदर्य और शक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत में लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। जब आम नागरिकों को अपने सपनों की पूर्ति और विकास में भागीदारी दिखाई देती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार लगभग 90 प्रतिशत तक मतदान दर्ज किया गया, जो लोकतंत्र के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 16 मई की तारीख का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में इसी दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और दशकों बाद देश में स्थिर एवं पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि 13 वर्ष मुख्यमंत्री और 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में देश सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। करोड़ों देशवासियों का लगातार समर्थन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह बहुत छोटी उम्र में ही देशभक्ति के रंग में रंग गए थे। उन्होंने "अहम् से वयम्" का मार्ग चुना और अब जनता का सुख ही उनका सुख तथा जनता का कल्याण ही उनका कर्तव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल बदलाव नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने का सपना देख रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का नीदरलैंड में भव्य स्वागत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को यूरोपीय देश नीदरलैंड पहुंचे। यहां पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने शनिवार को इस शानदार स्वागत की कुछ झलकियां साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, "कल नीदरलैंड पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जो दिल को छू लेने वाला स्वागत किया, वह सचमुच बेहद खास था। प्रवासी भारतीयों का यह अपनापन, जोश और स्नेह अभिभूत करने वाला है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत की कुछ विशेष झलकियां और तस्वीरें भी साझा कीं। नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस असाधारण समारोह में भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनूठी झलक देखने को मिली। स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों ने देश के विभिन्न

हिस्सों की पारंपरिक नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां दीं। इनमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम सहित विभिन्न नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां शामिल थीं। इसमें गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी शामिल थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बताया था कि मैं एम्स्टर्डम पहुंच गया हूं। नीदरलैंड की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने व्यापार और निवेश संबंधों को काफी गति प्रदान की है। इससे सेमीकंडक्टर, जल, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलता है। मैं प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ बातचीत करूंगा और राजा विलेम-अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करूंगा। यह यात्रा भारत और नीदरलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की पांच देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं।

नीट यूजी पेपर लीक मामला

सीबीआई ने जीव विज्ञान पेपर लीक की कथित मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान विषय के प्रश्न लीक करने की कथित मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने पुणे की वनस्पति विज्ञान शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडारे को यहां से गिरफ्तार कर लिया। वह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट-यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थीं। सीबीआई ने बताया कि मनीषा मंडारे को वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्रों तक पूरी पहुंच थी। जांच में सामने आया है कि अप्रैल महीने में उसने पुणे की मनीषा वाघमारे के माध्यम से संभावित अभ्यर्थियों को जुटाया और अपने पुणे स्थित आवास पर विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित कीं। मनीषा को पहले ही 14 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी के अनुसार इन कक्षाओं के दौरान उन्होंने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान से जुड़े कई प्रश्न अभ्यर्थियों को बताए तथा उन्हें अपनी कॉपियों और पाठ्य पुस्तकों में चिह्नित करने को कहा। बाद में इनमें से अधिकांश प्रश्न 03 मई को आयोजित वास्तविक नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। सीबीआई ने पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में 06 स्थानों पर छापेमारी भी की। कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक विवरण और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। सीबीआई ने 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल गठित किए गए और देशभर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। एजेंसी ने बताया कि अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से पांच आरोपितों को अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दो अन्य आरोपितों को पुणे से पारगमन (ट्रांजिट) रिमांड पर दिल्ली लाया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। सीबीआई के अनुसार अब तक की जांच में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रश्नपत्र लीक का वास्तविक स्रोत तथा उन बिचौलियों की भूमिका सामने आई है।

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी ने विदेश यात्रा पर टैक्स की खबरों को बताया गलत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार द्वारा कोई नया टैक्स लगाने की खबरों

को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के द्वारा इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया। हालांकि, यह स्पष्टीकरण तब आया है जब महज कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं नागरिकों से देशहित में विदेश यात्राओं को टालने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने कहा कि विदेश यात्रा पर ऐसी कोई पाबंदी लगाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। यह खंडन उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में आया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि 10 और 11 मई को दो अलग-अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने की अपील की थी। हैदराबाद में 10 मई को उन्होंने देशहित में शादियों, छुट्टियों या अन्य कारणों से होने वाली विदेश यात्राओं को स्थगित करने का सुझाव दिया था। अगले दिन, 11 मई को वडोदरा में उन्होंने विशेष रूप से विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहा था कि वे खुद विदेश यात्रा से बचें और कम से कम पाँच विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाएँ। इन अपीलों के पीछे महंगे ईंधन और वैश्विक हालात के कारण भारत पर पड़ रहे आर्थिक दबाव का हवाला दिया गया था।

सिक्किम के 51वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,

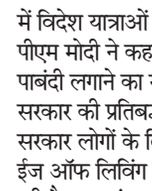

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और राज्य की उपलब्धियों की सराहना की। सिक्किम 16 मई 1975 को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था। राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सिक्किम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के कारण देश के लिए सतत विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। सिक्किम के लोग अपनी गर्मजोशी, सादगी और सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। राज्य निरंतर प्रगति करता रहे, यही उनकी कामना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्हें सिक्किम के लोगों के बीच राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का अवसर मिला, जहां मिली आत्मीयता उनकी स्मृतियों का हिस्सा बनी रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार आगे भी सिक्किम के विकास में पूरा सहयोग देती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिक्किम को कंचनजंगा की प्राकृतिक छटा, जैव विविधता और पूर्ण जैविक खेती वाले राज्य के रूप में देश की विशिष्ट पहचान बताया।

भारतीय वायुसेना द्वारा 'घातक' स्टेल्थ ड्रोन कार्यक्रम को तेज किया जाए

नई दिल्ली। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि देश में उन्नत दूर से संचालित मारक विमान तैयार करने के कार्यक्रम में तेजी लाने की दरकार है। दीक्षित ने कहा है कि ये विमान भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेंगे और उनकी मदद करेंगे। उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे 'लॉयल विंगमैन' कार्यक्रमों के साथ रफ्तार बनाए रखने के लिए न्यूनतम क्षमता हासिल करने की समय सीमा वर्ष 2030 तय की। उन्होंने नई दिल्ली में एरोस्पेस पावर ऐंड स्ट्रैटजिक स्टडीज सेंटर द्वारा आयोजित मानव रहित हवाई प्रणालियों एवं उनसे निपटने के तरीकों पर एक सेमिनार में कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के स्वदेशी 'घातक'

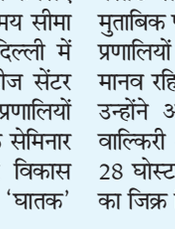

स्टेल्थ आरपीएसए कार्यक्रम को 'तत्काल गति' दी जानी चाहिए। भविष्य में आईएएफ के अभियानों में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान शामिल हो सकते हैं जो कई घातक आरपीएसए के साथ वास्तविक समय में तालमेल स्थापित करेंगे। इनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और लक्ष्यीकरण सेंसर से लेकर सटीक गोला-बारूद तक विभिन्न मिशन पेलोड ले जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक लड़ाकू विमानों को स्वायत्त प्रणालियों के साथ जोड़ने की अवधारणा को मानव रहित टीमिंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अमेरिका के क्रैटोस एक्सक्यू -58 वाल्किरी और ऑस्ट्रेलिया के बोइंग एमक्यू-28 घोस्ट बैट जैसे लॉयल विंगमैन कार्यक्रमों का जिक्र किया।

पेट्रोल-डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी और बढ़ सकते हैं दाम

एजेंसी। नई दिल्ली

अभी भी हर लीटर पर कंपनियों को हो रहा 39 रुपए प्रति लीटर का नुकसान

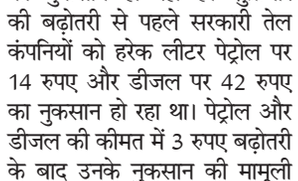

पश्चिम एशिया में पिछले ढाई महीने से जारी संकट के चलते कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है। यह 130 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था और अब भी लगातार 100 डॉलर के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ 0का नुकसान हो रहा था। सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। चार साल में पहली बार पेट्रोल-डीजल की कीमत को बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें अभी और बढ़ोतरी हो रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी के हमले के बाद से कच्चे तेल की कीमत 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ी हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत और बढ़ सकती हैं। इंटस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि दाम बढ़ने के बावजूद पेट्रोल में अब भी 11 रुपए और डीजल में 39 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। शुक्रवार की बढ़ोतरी से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हरेक लीटर पेट्रोल पर 14 रुपए और डीजल पर 42 रुपए का नुकसान हो रहा था। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए बढ़ोतरी के बाद उनके नुकसान की मामूली भरपाई हो सकती है। पूरी तरह घाटे से उबरने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी इजाफा करना होगा। इस बीच सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर लगाया है जबकि डीजल पर कर घटाकर 16.5 रुपए प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर कर घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया। नई दरें शनिवार 16 मई से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया है।

एनसीबी ने 182 करोड़ रुपये का कैप्टागॉन किया जब्त, सीरियाई नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 'ऑपरेशन रेजपिल' के तहत एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी

गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 227.7 किलोग्राम कैप्टागॉन की गोलियां और चूर्ण जब्त किया है। जब्त किये गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 182 करोड़ रुपये बताई गई है। मामले में सीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस कार्रवाई के लिए एनसीबी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि 'ऑपरेशन रेजपिल' के माध्यम से भारत में पहली बार कैप्टागॉन नामक मादक पदार्थ की जब्ती की गई है। मोदी सरकार 'नशामुक्त भारत' के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत को मादक पदार्थों के पारगमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि विदेशी मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी से मिली सूचना के आधार पर एनसीबी ने 11 मई को दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय क्षेत्र में एक मकान पर छापा मारा।

ट्रंप की हत्या पर मिलेगा 50 मिलियन यूरो, ईरानी संसद में पेश होगा प्रस्ताव

तेहरान। ईरानी मीडिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खबर ने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सरकार ट्रंप की हत्या के बदले 50 मिलियन यूरो के इनाम का एक प्रस्ताव संसद में लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा "काउंटर-एक्शन" नामक योजना का मसौदा तैयार किए जाने की घोषणा की है। इस मसौदे में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो का इनाम देने

का प्रस्ताव शामिल है अजीजी ने कहा कि ट्रंप, इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर को काउंटर-एक्शन के लिए टारगेट किया जाना चाहिए। अजीजी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या में इनकी भूमिका की वजह से उन्हें टारगेट करने की बात कही। सरकार के सपोर्टर अली अकबर ने पहले दावा किया था कि "किल ट्रंप" नाम के कैंपेन के लिए 50 मिलियन डॉलर के वित्तीय रिसोर्स सुरक्षित कर लिए गए हैं। एक हैकिंग ग्रुप ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि समूह ने ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए 50 मिलियन डॉलर दिए।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

भारतीय न्यायपालिका की चर्चा सारी दुनिया में

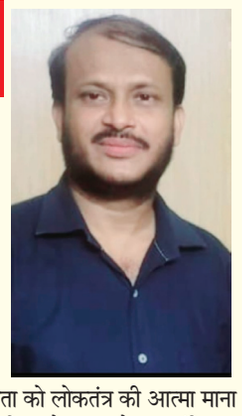

भारतीय न्यायपालिका को लंबे समय तक लोकतंत्र के सबसे विश्वसनीय स्तंभ के रूप में देखा जाता रहा है। दुनिया भर में भारत की न्याय व्यवस्था की चर्चा इसलिए होती थी क्योंकि यहां लिखित संविधान, स्थापित विधिक परंपराएं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना गया। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी इस बात का प्रतीक थी कि अदालतें बिना भेदभाव, केवल संविधान और कानून के आधार पर न्याय करेंगी। यही कारण था कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के अनेक ऐतिहासिक फैसलों ने भारतीय न्यायपालिका को वैश्विक सम्मान दिलाया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका के कामकाज को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आलोचना के केंद्र में यह धारणा बनी है, कि अदालतें अब पहले जैसी निर्भीक और जनविश्वास की प्रतीक नहीं रह गई हैं।

आम लोगों के बीच यह भावना गहराने लगी है कि कई संवेदनशील मामलों में सुनवाई और फैसलों का समय सरकारों की राजनीतिक सुविधा के अनुसार तय होता दिखाई देता है। न्यायपालिका का दायित्व केवल कानून की व्याख्या करना नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। यदि यही भरोसा कमजोर पड़ने लगे, तो लोकतंत्र की नींव भी प्रभावित होती है। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका की अवधारणा को विस्तार देते हुए आम नागरिकों के लिए न्यायालयों के द्वार खोल दिए थे। पोस्टकार्ड और साधारण पत्रों के माध्यम से भी लोगों को न्याय मिलने लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाला फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। उस दौर में अदालतों ने कई बार सरकारों के खिलाफ कठोर फैसले दिए और नागरिक अधिकारों की रक्षा की।

वर्तमान की बात करें तो आज की स्थिति कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में वर्षों तक सुनवाई लंबित रहती है। चुनाव, नागरिक अधिकार, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आधार पर बनाए गए कानूनों जैसे विषयों पर समयबद्ध फैसले न आने से न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठते हैं। यदि किसी मामले का निर्णय तब आए जब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका हो, तो न्याय की सार्थकता भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि देरी से मिला न्याय भी न्याय नहीं रह जाता है। न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं।

जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप, महाभियोग की जटिल प्रक्रिया और इस्तीफों के बाद कार्रवाई का समाप्त हो जाना लोगों के मन में असमंजस पैदा करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र में कोई भी संस्था आलोचना से ऊपर नहीं हो सकती। हाल के वर्षों में अदालतों में सुनवाई के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों ने भी बहस को जन्म दिया है। न्यायाधीशों की टिप्पणियां यदि सामाजिक या राजनीतिक रूप से पक्षधर प्रतीत हों, तो आम नागरिकों का विश्वास प्रभावित होता है। बेरोजगारी, पेपर लीक, लंबित नियुक्तियां और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर युवा वर्ग में पहले से ही असंतोष व्याप्त है। ऐसे समय में अदालतों से संवेदनशील और संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा स्वाभाविक है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि संविधान ने न्यायपालिका को सबसे कमजोर नागरिक की रक्षा का दायित्व सौंपा है। विधायिका और कार्यपालिका स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली संस्थाएं होती हैं, जबकि आम नागरिक अक्सर उन्हीं से संघर्ष करते हुए अदालतों तक पहुंचता है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

चीन से खाली हाथ अमेरिका लौटे ट्रंप

एजेंसी। वाशिंगटन

- **दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त बयान तक जारी नहीं किया**
- **ट्रंप के ऑफर पर मौन रहे जिनपिंग, ईरान और होर्मुज पर भी नहीं हो सका फैसला**

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप तीन दिवसीय चीन दौरे के बाद शुक्रवार को अमेरिका लौट गए। उन्होंने अपनी यात्रा को "ऐतिहासिक" और "बेहद सफल" बताया, लेकिन छह दौर की बैठकों के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच किसी बड़े समझौते या संयुक्त बयान की घोषणा नहीं हो सकी। इस वजह से दौरे के वास्तविक परिणामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता में ईरान युद्ध, ताइवान, ट्रेड-टैरिफ विवाद, रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों ने कई समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रगति की है और द्विपक्षीय संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी ठोस सहमति या समझौते का स्पष्ट विवरण नहीं दिया। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ईरान युद्ध और व्यापारिक तनाव के बीच इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। करीब नौ वर्षों बाद चीन पहुंचे ट्रंप के साथ 17 बड़े अमेरिकी कारोबारी भी गए थे, जिससे बोइंग विमान सौदे, कृषि खरीद, कर्ज सहयोग और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़े व्यापारिक एलानों की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि यात्रा समाप्त होने तक इन मुद्दों पर कोई औपचारिक समझौता सामने नहीं आया। इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत गर्मजोशी देखने को मिली। चीन ने ट्रंप के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया, स्टेट डिनर आयोजित किया और झोंगनानहाई में विशेष मेजबानी कर संबंधों में स्थिरता का संकेत देने की कोशिश की। चीन यात्रा के बाद दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश और 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हुए हैं। हालांकि चीन की ओर से इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। चीनी सरकार ने केवल व्यापक सहयोग, स्थिरता और शांति बनाए रखने की बात कही। ईरान युद्ध को लेकर भी ट्रंप ने कहा कि उनकी और शी जिनपिंग की सोच समान है। उनके अनुसार दोनों देश चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहे और ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके।

ख़ास ख़बर

डेटिंग एप से दोस्ती, फिर वीडियो कॉल कर करता था ब्लैकमेल, आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने डेटिंग एप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर सेक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के डीग जिले से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड और करीब 150 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हीं वीडियो की मदद से आरोपी देशभर के लोगों को ब्लैकमेल कर रुपये वसूलता था। गिरफ्तार आरोपित की पहचान अरमान (23) निवासी गांव लडामका, डीग, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और गिरोह से जुड़े बैंक खातों की जांच कर रही है। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त राजेन्द्र प्रसाद मीणा ने शनिवार को बताया कि 13 मई को एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर वसूली से जुड़ी एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपितों ने पहले डेटिंग एप के जरिए उससे संपर्क किया और दोस्ती बढ़ाई। इसके बाद पीड़ित को एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल की गई। वीडियो कॉल के दौरान आरोपितों ने पहले से रिकॉर्ड अश्लील वीडियो चलाए और पीड़ित को भी अश्लील हरकतें करने के लिए उकसाया। इस दौरान उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई। बाद में उसी वीडियो के आधार पर पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। आरोपी धमकी देने लगे कि यदि रुपये नहीं दिए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। डर के कारण पीड़ित ने आरोपितों को करीब एक लाख रुपये दे दिए। इसके बावजूद आरोपित लगातार और रकम मांगते रहे। परेशान होकर पीड़ित ने मामले की शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर की। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना में तैनात इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और उन बैंक खातों की जांच की, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस टीम राजस्थान के डीग पहुंची और वहां से आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध कबूल कर लिया।

कांग्रेस ने महंगाई और ईंधन के बढ़े दामों के खिलाफ किया प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी में मंहगाई और बढ़ी ईंधन की कीमतों के खिलाफ बैलगाडी चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शनिवार को करोल बाग स्थित पेट्रोल पंप पर ईंधन की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बैलगाड़ी चलाकर विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की विफल नीतियों के कारण उपजी कमरतोड़ महंगाई से आम जनता त्रस्त है। इस दौरान करोल बाग दिल्ली कांग्रेस महासचिव अनिल भारद्वाज, जिलाध्यक्ष महेंद्र भास्कर, जगजीवन शर्मा, राहुल धनक , सुनील कुमार मौजूद रहे। अनिल भारद्वाज ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ने यह साबित कर दिया है कि महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। उन्होंने कहा कि दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीज महंगी होने का असर सीधे हर घर की रसोई पर पड़ता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर परिवार इसका बोझ महसूस कर रहा है। वहीं पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ सफर महंगा नहीं होता, बल्कि परिवहन खर्च बढ़ने के कारण खाने-पीने की चीजों, सब्जियों, राशन और अन्य जरूरी सामान की कीमतों पर भी असर पड़ता है। सरकार विकास और आर्थिक मजबूती के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आम आदमी का घर चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

सिंधु जल पर मध्यस्थता न्यायालय अवैध, फैसले का कोई मतलब नहीं: भारत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारत ने सिंधु जल से संबंधित मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि उसने इसे कभी मान्यता नहीं दी है। इसका अर्थ है कि उसकी ओर से जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को कहा कि 15 मई को अवैध रूप से गठित तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने सिंधु जल संधि की व्याख्या से जुड़े मामले में एक अतिरिक्त फैसला जारी किया। यह फैसला परियोजनाओं में पानी के अधिकतम भंडारण से संबंधित मुद्दे पर दिया गया है।उन्होंने कहा कि भारत इस तथाकथित फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अवैध रूप से गठित सीओए के सभी पिछले फैसलों को दृढ़ता से खारिज किया है। भारत ने इस तथाकथित सीओए की स्थापना को कभी मान्यता नहीं दी है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। यह संधि 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। संधि के तहत- पूर्वी नदियों (रावी, व्यास, सतलज) का पानी भारत के उपयोग के लिए है, जबकि पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था।

सोशल मीडिया पर हथियारों संग फोटो डालना पड़ा भारी, मेरठ का हथियार सप्लायर गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए मेरठ के एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। जबकि सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वाले एक नाबालिग को भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में अब तक कुल दो पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने शनिवार को बताया कि यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 0122/2026, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान की गई। इससे पहले 9 मई को सोनिया विहार निवासी नवीन उर्फ विवेक को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ के दौरान नवीन ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी दी थी।नवीन ने पुलिस को बताया कि वह मेरठ से हथियार खरीदता था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की सदर्न रेंज टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना तंत्र के जरिए मेरठ निवासी दानिश की पहचान की। पुलिस ने लगातार निगरानी के बाद 13 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि दानिश दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को अवैध हथियार सप्लाई करता था। वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। मेरठ के दिल्ली गेट थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त के अनुसार जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि एक नाबालिग सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहा था। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस पहले नवीन तक पहुंची और फिर पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। 14 मई को पुलिस ने उस नाबालिग को भी पकड़ लिया। वह तुगलकाबाद एक्सटेंशन का रहने वाला है और एसी रिपेयर की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना अब अपराधियों के लिए पहचान और नेटवर्क बनाने का जरिया बनता जा रहा है। इसी वजह से ऐसे अकाउंट्स पर विशेष नजर रखी जा रही है।

सरकार के प्रयासों से लॉजिस्टिक्स सुगमता में दिल्ली ने हासिल किया सर्वोच्च स्थान : रेखा गुप्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता (लीड्स 2025) इंडेक्स में राजधानी दिल्ली को देश की सर्वोच्च अनुकरणीय (इग्जेम्प्लर) श्रेणी में जगह मिलने को गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दिल्ली सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने, व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि लीड्स 2025 इंडेक्स की रिपोर्ट 13 मई को जारी हुई है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जानकारी दी कि लीड्स इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, नियामकीय व्यवस्था, डिजिटल इंटीग्रेशन, स्थिरता और हितधारकों की धारणा जैसे प्रमुख मानकों पर करता है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों, इग्जेम्प्लर, हाई परफॉर्मर, एक्सेलरेटर्स और ग्रोथ सीकर्स में रखा जाता है, जिनमें 'इग्जेम्प्लर' सबसे ऊंची श्रेणी है। दिल्ली ने लगातार प्रगति करते हुए लीड्स 2023 और 2024 में 'अचीवर' श्रेणी से आगे बढ़कर इस वर्ष देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। इससे शहरी माल परिवहन, अंतिम चरण की डिलीवरी व्यवस्था और शहरी फ्रेट मैनेजमेंट को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर 46 अनिवार्य लेयर्स में से 38 का सफल इंटीग्रेशन किया जा चुका है। साथ ही 317 अतिरिक्त लेयर्स भी जोड़ी गई हैं। इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वित इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निवेश से जुड़ी स्वीकृतियों एवं अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। वहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के जरिए एपीआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एक्सचेंज की सुविधा विकसित की गई है, जिससे विभिन्न लॉजिस्टिक्स हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाए गए पॉटहोल-फ्री रोड अभियान के तहत दिल्ली की मुख्य और आंतरिक सड़कों में बड़े स्तर पर सुधार किया गया है। साथ ही देश की पहली रिजनल रेपिड ट्रांजिट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) नमो भारत कॉरिडोर के संचालन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्री और माल परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के फेज-IV विस्तार, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे लिंक भी शामिल है, से राजधानी में मल्टीमॉडल शहरी परिवहन को नई गति मिली है। साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (यूईआर-II) और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे माल परिवहन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। डिजिटल सिस्टम और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के उपयोग में दिल्ली का प्रदर्शन राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के औसत से बेहतर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को अंतिम रूप दे रही है। इस नीति का उद्देश्य माल ढुलाई में भीड़भाड़ कम करना, नियामकीय जटिलताओं को दूर करना और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पॉलिसी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग ढांचे में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं डीटीसी और देवी बस सेवा के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर सड़क यातायात और माल परिवहन दबाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली औद्योगिक नीति के जरिए लॉजिस्टिक्स निवेश और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2025 में डीएमआरसी मेट्रो-कार्गो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्लू डार्ट के साथ साझेदारी कर नॉन-पीक घंटों में मेट्रो के जरिए पार्सल परिवहन शुरू किया गया है, जिससे सड़कों पर निर्भरता कम होगी और रोड कॉरिडोर पर दबाव घटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कुशल मानव संसाधन निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की नीतियों के माध्यम से सूक्ष्म एवं कारीगर आधारित उद्योगों को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। वहीं दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू), आईआरआईएलएमएम और ट्रांसग्लोब एकेडमी जैसे संस्थानों के जरिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के मामले में भी दिल्ली का प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेशों के औसत से बेहतर रहा है, जिससे राजधानी देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स ह्यूमन कैपिटल हब के रूप में उभर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लीड्स 2025 में दिल्ली ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, संचालन एवं नियामकीय व्यवस्था तथा स्थिरता एवं समानता जैसे सभी प्रमुख मानकों पर राष्ट्रीय और यूटी औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, डिजिटल सिस्टम, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में दिल्ली को मजबूत अंक प्राप्त हुए हैं। परिवहन सेवाएं, टर्मिनल सेवाएं और कुशल मानव संसाधन के मामले में भी दिल्ली का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। साथ ही अंतरराज्यीय माल परिवहन सुगमता और नीति सुधारों में भी दिल्ली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हालांकि शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता को भी चिन्हित किया गया है, जिस पर सरकार गंभीरता से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना दिल्ली सरकार की आगामी प्राथमिकताओं में शामिल है। दिल्ली सरकार अब राजधानी में संगठित ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे अनियंत्रित सड़क किनारे लोडिंग को कम किया जा सके और माल परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बने। दिल्ली सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का उपयोग रात और नॉन-पीक घंटों में हल्के माल परिवहन के लिए बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि सड़क कॉरिडोर पर दबाव कम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर कार्गो टर्मिनलों में मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर उत्पादकता और दक्षता में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों से जुड़े मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाएंगे, जहां प्रथम और अंतिम चरण की कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बस फीडर सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

सलाम किसान : कृषि-ड्रोन, किसानो के लिए वरदान फ्रेंचाइज़ की पहल

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: भारत में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सलाम किसान, जो प्राइम समूह का आधुनिक कृषि मंच है, ने देशभर में कृषि-ड्रोन व्यवसाय से क्रांति लाने के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए इसका फ्रेंचाइज़ मॉडल शुरू किया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित फ्रेंचाइज़ इंडिया 2026 प्रदर्शनी में की गई। कंपनी का लक्ष्य पहले चरण में देशभर के 100 से अधिक जिलों में कृषि-ड्रोन सेवा केंद्र स्थापित करना है। इस पहल के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों के युवाओं और उद्यमियों को आधुनिक कृषि सेवाओं से जोड़कर अपने जिले में कृषि-तकनीक आधारित व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा। इन सेवा केंद्रों के माध्यम से किसानों को ड्रोन द्वारा दवाई और खाद का सटीक छिड़काव, फसल की निगरानी, खेतों की मैपिंग, कीट एवं रोग पहचान, आधुनिक कृषि मशीनरी सेवाएँ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खेती समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। धनश्री मंधानी, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने कहा: भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का लगभग 16 प्रतिशत योगदान है और देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। सलाम किसान का मानना है कि तकनीक आधारित खेती से किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन सुधारने और खेती की लागत कम करने में क्रृषि ड्रोन काफ़ी मददगार होगा।

जमाअत के अध्यक्ष ने कमाल मौला मस्जिद के फ़ैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की

» साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता की अपील की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फ़ैसले पर गहरी चिंता जताई है जिसमें कमाल मौला मस्जिद को मंदिर घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सौहार्द और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर गंभीर परिणाम होंगे। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के अध्यक्ष ने कहा, "यह फ़ैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल खड़े करता है। दशकों तक, भोजशाला परिसर एक ऐसे प्रबंधन के तहत संचालित होता रहा जिसने दोनों समुदायों को अपनी-अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति दी। एक समुदाय के स्थापित इबादत के अधिकारों को हटाकर दूसरे समुदाय को प्राथमिकता देना न केवल एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के सिद्धांत को भी कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है। इस तरह के घटनाक्रमों को अत्यंत सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए, और भारत जैसे बहुलवादी एवं विविध समाज में अपेक्षित नाजुक संतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

डमी फर्मों के जरिए करोड़ों के जीएसटी-वैट फर्जीवाड़े का खुलासा, सीए समेत दो गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने डमी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये के जीएसटी और वैट फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजीव कुमार परासर और चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन को अंजाम दिया तथा धन की लेयरिंग कर असली लाभार्थियों और वित्तीय ट्रेल को छिपाने की कोशिश की।आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त सुबोध कुमार ने शनिवार को बताया कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में वर्ष 2020 में एफआईआर संख्या 85/2020 दर्ज की थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता यशश्वी शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी फर्म एम/एस स्वास्तिक एंटरप्राइजेज के जीएसटी और वैट दस्तावेजों का बिना अनुमति इस्तेमाल कर करीब 28.4 करोड़ रुपये के संदिग्ध कारोबारी लेनदेन किए गए। शिकायत में कहा गया था कि अज्ञात लोगों ने उनकी फर्म के दस्तावेजों और क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग कर फर्जी कारोबार दिखाया और कई बैंक खातों के माध्यम से भारी रकम का लेनदेन किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एम/एस स्वास्तिक एंटरप्राइजेज के नाम से संचालित बैंक खातों का इस्तेमाल करोड़ों रुपये की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने और उसकी लेयरिंग करने के लिए किया जा रहा था।पुलिस के अनुसार, अलग-अलग कंपनियों और फर्मों से खातों में पैसा आने के तुरंत बाद उसे नकद निकाल लिया जाता था या फिर आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अन्य खातों में भेज दिया जाता था। जांच एजेंसी को इन लेनदेन के पीछे किसी वास्तविक कारोबारी गतिविधि के सबूत नहीं मिले। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी डमी फर्मों और फर्जी खातों का संचालन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इन फर्मों को कथित तौर पर बिचौलियों और फर्जी मालिकों के नाम पर बनाया गया था। आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये को अलग-अलग खातों में घुमाकर असली लाभार्थियों तक पहुंच छिपाई जाती थी। पुलिस उपायुक्त के अनुसार जांच के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गुप्ता और उनकी फर्म एम/एस अशोक अतुल एंड कंपनी की भूमिका भी सामने आई। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध फर्मों के जीएसटी रिटर्न और अन्य वैधानिक अनुपालन इसी फर्म के माध्यम से दाखिल किए जा रहे थे। जांच एजेंसी को यह भी जानकारी मिली कि कुछ फर्मों के जीएसटी बकाया और जुर्माने कर्मचारियों के निजी खातों से जमा कराए गए और बाद में वह रकम उन्हें वापस कर दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित लंबे समय तक जांच से बचते रहे। विशेष रूप से राजीव कुमार परासर काफी समय तक फरार रहा और लगातार ठिकाने बदलता रहा। तकनीकी निगरानी, बैंकिंग रिकॉर्ड, जीएसटी दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपितों को 12 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने रिमांड हासिल किया। अब आरोपितों से पूछताछ कर पूरे वित्तीय नेटवर्क, सह-साजिशकर्ताओं और धन के स्रोत की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उपायुक्त के अनुसार, आरोपित जीएसटी और वैट दस्तावेजों का दुरुपयोग कर डमी फर्मों के जरिए फर्जी कारोबार दिखाते थे। बैंक खातों में बड़ी रकम आने के बाद उसे तुरंत अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था या नकद निकाल लिया जाता था, ताकि असली लेनदेन और लाभार्थियों का पता न चल सके। आरोपित राजीव कुमार परासर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला है और बचपन में दिल्ली आ गया था। उसने दिल्ली से बीकॉम और मेरठ से एमकॉम की पढ़ाई की।शुरुआती दौर में वह अकाउंटिंग फर्मों में काम करता था और बाद में शाहदरा और दिलशाद गार्डन इलाके में एम/एस एमएम इंडस्ट्रीज और एम/एस स्वास्तिक एंटरप्राइजेज के नाम से कारोबार शुरू किया। पुलिस जांच में सामने आया कि उसकी फर्म के बैंक खाते का इस्तेमाल वर्ष 2021 तक संदिग्ध कंपनियों के करोड़ों रुपये के लेनदेन के लिए किया जाता रहा। वहीं, आरोपित अतुल गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है और वर्ष 2002 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। वह चांदनी चौक स्थित एम/एस अशोक अतुल एंड कंपनी से जुड़ा है, जिसकी स्थापना उसके पिता ने की थी। बाद में वह इसी फर्म के जरिए प्रैक्टिस करने लगा। जांच में पता चला कि उसकी फर्म और कर्मचारी संदिग्ध कंपनियों के जीएसटी रिटर्न और अन्य वैधानिक कामकाज संभालते थे। वहीं पुलिस ने लोगों, कारोबारियों और पेशेवरों से अपील की है कि वे अपने जीएसटी, पैन, आधार, डिजिटल सिग्नेचर और कारोबारी दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस और संबंधित एजेंसियों को दें।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने 'जल संचय अभियान' का किया शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को पश्चिम विहार स्थित जिला पार्क से 'जल संचय अभियान' का शुभारंभ किया। इसके तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 30 अगस्त तक दिल्ली के 101 महत्वपूर्ण जल निकायों को पुनर्स्थापित करने के लिए मिशन-मोड अभियान शुरू हो गया है।उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पहले चरण में मानसून के मौसम में भूजल पुनर्भरण को अधिकतम करने के लिए गहन गाद निकालने और जलग्रहण क्षेत्र की सफाई के माध्यम से कार्यात्मक पारिस्थितिक बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दीर्घकालिक जल सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह अभियान दिल्ली के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और शहर की पारिस्थितिक लचीलेपन को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जल निकायों को पुनर्स्थापित को समय-सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने और एक हरित, अधिक जल-सुरक्षित और पारिस्थितिक रूप से लचीली राजधानी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपराज्यपाल ने सभी निवासी से 'जन भागीदारी' के माध्यम से इस आंदोलन में भाग लेने और एक हरित, जल-सुरक्षित विकसित दिल्ली की दिशा में योगदान देने का आग्रह किया।

आईपीयू में "भारतीय ज्ञान परंपरा: निरंतरता, विच्छेद और समन्वय" पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स ने "भारतीय ज्ञान परंपरा: निरंतरता, विच्छेद और समन्वय" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की प्रभारी प्रो. क्वीनि प्रधान ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा (आईकेएस) के विकसित हो रहे क्षेत्र के इर्द-गिर्द आलोचनात्मक संवाद के लिए विभिन्न अनुशासनात्मक पृष्ठभूमियों के विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों को एक मंच पर लाना था। सम्मेलन में कई प्रतिष्ठित विद्वानों और प्रख्यात बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में प्रख्यात बुद्धिजीवी एवं आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी उपस्थित रहे। डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कला की सर्वव्यापकता और दैनिक जीवन की लय में ज्ञान परंपरा को उजागर करने पर बल दिया। प्रख्यात विज्ञान इतिहासकार प्रो. दीपक कुमार ने मुख्य भाषण दिया और सभी प्रकार के स्वदेशी ज्ञान के सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स का वार्षिक न्यूजलेटर 'नवकृति' भी जारी किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद राजनीतिक वैज्ञानिक प्रो. मधुलिका बनर्जी और समाजशास्त्री प्रो. विवेक कुमार की अध्यक्षता में विशेष संबोधन और तकनीकी सत्र आयोजित हुए। सम्मेलन के दूसरे दिन विविध प्रस्तुतियों पर गहन चर्चाएं हुईं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के संकाय प्रो. देव नाथ पाठक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. मणिंद्र नाथ ठाकुर और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रो. विवेक सचदेवा के बीच हुई गोलमेज चर्चा उपस्थित जनों के लिए विशेष आकर्षण रही। सम्मेलन के दो दिनों के दौरान भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विभिन्न विषयों और उप-विषयों पर आयोजित तकनीकी सत्रों में पूरे भारत से 30 से अधिक विद्वानों और शोधकर्ताओं ने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

संक्षिप्त समाचार

देशहित में सराफा व्यापारियों का बड़ा फैसला बुलियन गोल्ड की बिक्री रोकने पर जताई सहमति

कपिल सर्राफ के नेतृत में व्यापारी एक जुट

लोकतंत्र की शान , खिज़र अहमद ,नजीबाबाद बिजनौर। देश के प्रधानमंत्री की अपील पर बिजनौर जनपद के सराफा व्यापारियों ने देशहित में बड़ा निर्णय लेते हुए बुलियन गोल्ड की बिक्री न करने का संकल्प लिया। इस संबंध में ऑल इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, जीएसटी उपायुक्त संजय सिंह एवं जीएसटी उपायुक्त शैलेंद्र वार्ष्णेय मौजूद रहे। जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों को सरकार की मंशा एवं बुलियन गोल्ड की बिक्री रोकने के विषय में विस्तार से जानकारी दी। जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ ने कहा कि सराफा व्यापारी हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है और जब-जब देश पर कठिन परिस्थितियां आई हैं, तब-तब व्यापारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों से जो अपेक्षा की है, सराफा व्यापारी उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और बुलियन गोल्ड की बिक्री नहीं करेंगे। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि देशहित सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री की भावना का सम्मान करते हुए सभी व्यापारी सरकार के निर्णय में पूरा सहयोग देंगे। अधिकारियों ने भी व्यापारियों की इस पहल और आश्वासन की सराहना की। इस दौरान जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ ने अधिकारियों के समक्ष सराफा व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने एवं शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी जसजीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने व्यापारियों को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इसमें नजीबाबाद से मुकुल अग्रवाल, मयंक वर्मा, वैभव सर्राफ एडवोकेट, कीरतपुर से मुकुल अग्रवाल एवं डॉ. प्रखर अग्रवाल, धामपुर से अध्यक्ष योगेश रस्तोगी, अक्षत बंसल, अर्पित सिंघल, रामधनौरिया, पंकज अग्रवाल तथा बिजनौर से अध्यक्ष अतुल सर्राफ सहित बड़ी संख्या में सराफा व्यापारी उपस्थित रहे। अंत में सभी व्यापारियों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

साइकिल से कार्यालय पहुंचकर चेयरमैन कौसर अब्बास ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पेट्रोल-डीजल बचत और स्वच्छ वातावरण के लिए लोगों से की अपील

लोकतंत्र की शान , सैय्यद कुमैल जैदी , संभल सिरसी। बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक संकट को देखते हुए नगर पंचायत सिरसी के अध्यक्ष कौसर अब्बास ने शुक्रवार को एक अनोखी पहल करते हुए साइकिल से नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया। चेयरमैन के इस कदम की नगर में खूब सराहना हो रही है। अध्यक्ष कौसर अब्बास ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा देशहित में चलाए जा रहे बचत और पर्यावरण संरक्षण अभियानों से प्रेरणा लेकर उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि आम लोग छोटी-छोटी सुविधाओं में कटौती कर साइकिल और ई-वाहनों का अधिक प्रयोग करें तो देश की आर्थिक बचत के साथ-साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कार्यालय पहुंचने के बाद चेयरमैन ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया तथा सफाई व्यवस्था, पेयजल, सड़क मरम्मत और जनसमस्याओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। चेयरमैन कौसर अब्बास ने कहा कि साइकिल चलाना केवल स्वास्थ्य के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि इससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने नगरवासियों से अधिक से अधिक साइकिल और ई-वाहनों का उपयोग करने की अपील की। नगर पंचायत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने चेयरमैन के इस सराहनीय कदम को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार की पहल समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करती

रामपुर रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने वाले युवक की हुई शिनाख्त, पुष्पेंद्र सिंह निकला मृतक

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। उत्तर प्रदेश/ रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम पुष्पेंद्र सिंह (उम्र करीब 23 वर्ष) बताया गया है। वह ग्राम महुआ हसनपुर, थाना बरवाला, जिला संभल का निवासी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक रेलवे स्टेशन पर अपनी भाभी के साथ मौजूद था, इसी दौरान उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है, आगे की कार्रवाई जारी है।

भारतीय किसान संघ ने पांच सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार कार्यालय पर सौपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शनिवार को भारतीय किसान संघ जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया बैठक में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी संजीव कुमार शर्मा व ब्लाक प्रभारी व जिला मन्त्री आलोक कुमार चौहान मौजूद रहे, बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान ने की संचालन ब्लॉक उपाध्यक्ष कामेंद्र सिंह ने किया, बैठक का आयोजन तीन सत्रों में किया गया प्रथम सत्र में जिला प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने संगठन के विस्तार के बारे मे विस्तार से समझाया ओर संगठन को मजबूत किस प्रकार बनाया जाए विस्तार से बतलाया , वही द्वितीय सत्र में ब्लॉक मंत्री व खंड प्रभारी आलोक चौहान ने सदस्यता को पूरे खंड में करने का उपस्थित कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया तथा ब्लॉक अध्यक्ष से समस्त गांवों में संघ के कार्यकर्ता को गांवों की जिम्मेदारी सौंपकर लिस्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा, वही तृतीय सत्र में प्रांतीय गन्ना प्रमुख महीपाल सिंह ओर जिला कोषाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान ने बताया कि ब्लॉक कार्यकारणी के हर दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिला कार्यकारणी के सदस्यों को भी 4 से 5 गांवों की जिम्दमेदारी दी जाए, बैठक के उपरान्त पांच सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार के नाम संबोधित करते हुए नायाब तहसीलदार मनोज कुमार को सौंपा गया, बैठक के उपरान्त गांव रामपुर भूड़ में ग्राम समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिला प्रभारी का रात्रि प्रवास गांव मिर्जापुर डूंगर में ब्लाक कार्य कारिणी सदस्य जयप्रकाश शर्मा के आवास पर रहा, इस अवसर पर प्रांतीय युवा प्रमुख ओर जिला प्रभारी संजीव कुमार शर्मा, प्रांतीय गन्ना प्रमुख महीपाल सिंह, जिला मंत्री आलोक चौहान, जिला कोषाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, जिला युवा प्रमुख कपिल कुमार, जिला विद्युत प्रभारी यशपाल सिंह, जिला महिला प्रमुख ऊषा चौधरी, शारदा सिंह, कामेंद्र सिंह, हितेश चौधरी, मिस्री सिंह, गंगाराम मंत्री धर्मपाल सिंह राजीव सिंह, जयप्रकाश शर्मा, हाकम सिंह, लल्लू सिंह, जशमंत सिंह, ऋषिपाल, जितेंद्र सिंह, महीपाल सिंह आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे l

जनगणना कार्मिकों के फोटोयुक्त पहचान पत्र शीघ्र जारी किए जायें : संजय सिंह

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक मूंढापांडे की एक मीटिंग प्राथमिक विद्यालय चमरौआ में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। 1. जनगणना परिचय पत्र जारी किए जाये, क्षेत्र आवंटन बहुत कम और ज़्यादा है उसको ठीक किया जाए। 2. मुरादाबाद तहसील जनगणना एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में लगाई गई ड्यूटी संशोधित कर अपने विकास खंड में लगायी जाये जहाँ संबंधित कर्मचारी BLO भी रहा है महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए मुरादाबाद तहसील में जनगणना के नाम पर अध्यापकों का शोषण हो रहा है उस को तत्काल बंद किया जाये। 3. चयन वेतनमान इसी महीने लेखा कार्यालय में फीड करा दिए जाए जो जानबूझकर लेखा कार्यालय द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं समायोजन के नाम पर अध्यापकों का जो शोषण हो रहा है उसे बंद किया जाए और यदि अति आवश्यक है तब विकल्प के आधार पर किया गया जाये। नामांकन भी बढ़ाया जाए जिससे अपने पद सुरक्षित रह सके। बैठक की अध्यक्षता संजय कुमार सिंह ने की बैठक में रेनू यादव, गरिमा गुप्ता, सुरेन्द्र कुमार, विनोद यादव, राजीव सिंह, वेदप्रकाश, राजीव कुमार सिंह, देवेश चक्रवर्ती, सतेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, दुर्गेश कुमार सिंह, देश दीपक, पंकज कुमार, भूपेन्द्र कुमार, पराग यादव, मनोज यादव, अनिल कुमार, खगेन्द्र कुमार उपस्थित रहे संचालन ब्लॉक मंत्री हिमांशु वशिष्ठ ने किया।

मत करिए चिंता, उपचार कराने में भरपूर मदद देगी सरकार : सीएम योगी

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद की गुहार लेकर आए लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि उपचार कराने में सरकार भरपूर मदद करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि दी जाएगी। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने होंगे उनके कार्ड बनवाए जाएंगे। <गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक जाकर उनकी समस्याओं को सुना। उनके प्रार्थना पत्र लिए और पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद का अनुरोध करने आए थे। एक महिला ने अपने बच्चे के इलाज में आर्थिक दिक्कत और आयुष्मान कार्ड न होने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए। बच्चे का इलाज जरूर होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से इलाज में आर्थिक सहायता देंगे। एक अन्य महिला को भी उन्होंने इन्हीं शब्द भावों का आत्मीय संबल दिया। इलाज संबंधी प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शासन को उपलब्ध करा दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साइकिल से निकले चेयरमैन कौसर अब्बास, निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

लोक तंत्र की शान

सम्भल/सिरसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल-डीजल बचत एवं पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को गंभीरता से लेते हुए सिरसी नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास ने शुक्रवार को भीषण गर्मी के बीच साइकिल से नगर भ्रमण कर एक अलग मिसाल पेश की। चेयरमैन के इस सादगी भरे अंदाज को देखकर नगरवासियों ने उनकी जमकर सराहना की। चेयरमैन कौसर अब्बास ने नगर की विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों का साइकिल से पहुंचकर निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद ठेकेदारों को गुणवत्ता पूर्ण कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पंचायत की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने राहगीरों व स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अचानक दोपहर की तेज गर्मी में चेयरमैन को साइकिल चलाते देख लोग हैरान रह गए। नगरवासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच इसी तरह सादगी और जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। चेयरमैन कौसर अब्बास ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि प्रत्येक नागरिक छोटे-छोटे प्रयास करे तो देश को ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी सफलता मिल सकती है। उनके इस अनोखे और जनहितकारी कदम की नगर में पूरे दिन चर्चा होती रही।

गोरखपुर में बनेगा विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सः मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करने के साथ ही खेल व खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बगल में आरक्षित कराई गई 60 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में शनिवार को गोरखपुर के ताल नदोर में करीब 393 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां 46 एकड़ में 30 हजार दर्शकों की क्षमता का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो बनेगा ही, इसके बगल की 60 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। इसमें हर तरह के इनडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा हॉकी जैसे अन्य आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने से इस क्षेत्र में होटल, रेस्त्रां व मार्केट की नई श्रृंखला तैयार होगी और बड़ी संख्या में नए रोजगार भी सृजित होंगे।

लोक कल्याण के लिए होना चाहिए सरकारी भूमि का उपयोग- मुख्यमंत्री ने ताल नदोर क्षेत्र में हो रहे विकासपरक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ साल पहले यह क्षेत्र बंजर पड़ा था। उपेक्षित था, जिसकी मर्जी होती वह कब्जा कर लेता था। अब यहां की जमीन कब्जामुक्त है। डबल इंजन सरकार इस भूमि पर नौजवानों के भविष्य को तराशने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम युवाओं और भावी पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। सरकारी भूमि का उपयोग लोक कल्याण तथा विकास परियोजनाओं के लिए होगा। इसी विजन से ताल नदोर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है।

जाति-क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले नहीं हो सकते जनता के हितैषी-सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को माफियामुक्त, गुंडामुक्त, दंगामुक्त, कर्फ्यूमुक्त बनाया है। इससे प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव से होता है। जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग जनता के हितैषी नहीं हो सकते। जब ऐसे लोगों को सत्ता मिली तो वे गुंडागर्दी, अराजकता, अव्यवस्था फैलाते रहे। जनहित के बजाय परिवार के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते रहे। लेकिन, डबल इंजन सरकार जन कल्याण व रोजगार सृजन के लिए कार्य कर रही है।

ई-रिक्शा पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे शहर विधायक आकाश सक्सेना, लोगों में चर्चा का विषय बना दौरा

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश/ शहर विधायक आकाश सक्सेना एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में आ गए। विधायक आकाश सक्सेना शुक्रवार को ई-रिक्शा पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके इस सादगी भरे अंदाज को देखकर आम लोगों में काफी चर्चा रही। बताया जा रहा है कि विधायक आकाश सक्सेना किसी सरकारी कार्य एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और उनके साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। विधायक का ई-रिक्शा से कलेक्ट्रेट पहुंचना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि विधायक का यह अंदाज आम जनता से जुड़ाव को दर्शाता है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद विधायक ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर जनसमस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर बातचीत की।

शहर में चर्चा का विषय बना दौरा-ई-रिक्शा पर कलेक्ट्रेट पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। समर्थकों का कहना है कि विधायक आकाश सक्सेना हमेशा जनता के बीच रहकर काम करने वाले नेता हैं।

बरेली में पेट्रोल-डीजल बचत का संदेश देने ई-रिक्शा पर निकले वन मंत्री अरुण सक्सेना

» मंत्री ने छोड़ी सरकारी गाड़ी, बोले- "ईंधन बचाना समय की जरूरत", ईरान-इजरायल तनाव के बीच जनता से की अपील

लोक तंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) देश में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अब जनप्रतिनिधि भी मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री Arun Kumar Saxena ने सरकारी गाड़ी छोड़ ई-रिक्शा से शहर भ्रमण कर लोगों को पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश दिया। शहर की सड़कों पर मंत्री को ई-रिक्शा में सफर करता देख लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाए तो कुछ ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समय की जरूरत बताया। मंत्री ने कहा कि आज दुनिया जिस तरह ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय तनाव से गुजर रही है, उसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह ईंधन बचाने में योगदान दे। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री Yogi Adityanath लगातार पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ई-रिक्शा का इस्तेमाल कर जनता को संदेश देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। दुनिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर सीधे ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि समुद्री मार्गों पर संकट गहराने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा।

'ई-बस में पहुंचे डीएम अविनाश सिंह, तहसील दिवस बना मिसाल'

लोक तंत्र की शान

» PM मोदी और CM योगी की अपील का असर, बरेली प्रशासन ने दिया ईंधन बचत और सादगी का संदेश

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब जिलाधिकारी अविनाश सिंह अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ ई-बस से तहसील पहुंचे। आमतौर पर अधिकारियों के लंबे काफिले और सरकारी वाहनों की भीड़ देखने वाले लोगों को इस बार एक अलग तस्वीर देखने को मिली। जिलाधिकारी की इस पहल ने न सिर्फ ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, बल्कि प्रशासनिक सादगी और जिम्मेदारी की नई मिसाल भी पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और अनावश्यक सरकारी खर्च में कटौती की अपील की जाती रही है। बरेली प्रशासन ने अब इन संदेशों को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। शनिवार सुबह जब जिलाधिकारी अविनाश सिंह ई-बस से तहसील परिसर पहुंचे तो उनके साथ एडीएम, डीएसओ, डीपीआरओ सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों को एक साथ सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से पहुंचता देख तहसील परिसर में मौजूद फरियादी, अधिवक्ता और आम लोग हैरान रह गए। लोगों ने इसे प्रशासन की सकारात्मक सोच बताते हुए डीएम की जमकर सराहना की। तहसील परिसर में मौजूद कई लोगों ने कहा कि आमतौर पर अधिकारी बड़े काफिले और सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचते हैं, लेकिन डीएम अविनाश सिंह ने बेहद सादगीपूर्ण तरीके से ई-बस में यात्रा कर यह दिखा दिया कि सरकारी पद का मतलब दिखावा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। लोगों ने इसे "जनता के करीब प्रशासन" की तस्वीर बताया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अविनाश सिंह पहले भी अपने अलग फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले डीजल की बचत और अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से अपनी दोनों एस्कॉर्ट गाड़ियों को हटाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से भी सरकारी वाहनों का कम से कम उपयोग करने और वैकल्पिक साधनों को अपनाने की अपील की थी। अब उनकी इस पहल का असर प्रशासनिक व्यवस्था में साफ दिखाई देने लगा है। कई अधिकारी साइकिल, शेयरिंग वाहन और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रशासनिक हलकों में इसे "ग्रीन प्रशासन मॉडल" के तौर पर देखा जा रहा है। ई-बस से तहसील पहुंचने के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। राजस्व, पुलिस, विकास और आपूर्ति विभाग से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ किया जाए। समाधान दिवस के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि शेष मामलों के लिए संबंधित विभागों को समय सीमा तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम अविनाश सिंह की इस अनोखी पहल की चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ई-बस में सफर कर उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि यदि सरकारी व्यवस्था खुद बदलाव अपनाएगी, तभी समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा। ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर बरेली प्रशासन की यह पहल अब दूसरे जिलों के लिए भी एक उदाहरण बनती दिखाई दे रही है।

संक्षिप्त समाचार

वैशाली में समाहरणालय की पार्किंग रही खाली

लोकतंत्र की शानः हाजीपुर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 'नो व्हीकल डे' के आह्वान का असर शनिवार को वैशाली में दिखा। जिलाधिकारी वर्षा सिंह समेत कई अधिकारी पैदल और ई-रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे। समाहरणालय परिसर में वाहन पार्किंग स्थल खाली रहा। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने वैशाली जिला वासियों से अपील की कि वे सरकार के इस आह्वान का पालन करें। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन ई-रिक्शा, पैदल या साइकिल से कार्यालय आएं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि ईंधन का कम से कम उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन 'नो फ्यूल डे' मनाया जाए। जिलाधिकारी स्वयं अपने आवास से त्रिमूर्ति चौक तक ई-रिक्शा से आईं और वहां से गांधी चौक होते हुए अधिकारियों के साथ पैदल कार्यालय पहुंचीं। यह निर्णय मध्य-पूर्व क्षेत्र में उत्पन्न भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण लिया गया है। इन परिस्थितियों के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीजल-पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों का कम उपयोग करने और सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री की अपील के बाद शनिवार को जिलाधिकारी वर्षा सिंह के साथ एडीएम संजय कुमार, डीडीसी कुंदन कुमार और एसडीओ राम बाबू बैठा सहित कई अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी ई-रिक्शा, साइकिल या पैदल कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन न होने के कारण समाहरणालय परिसर का पार्किंग स्थल पूरी तरह खाली रहा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को सभी अधिकारी और कर्मचारी ईंधन की बचत करते हुए कार्यालय आएंगे। उन्होंने कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही। डीएम ने आम लोगों से भी ईंधन का कम इस्तेमाल करने, पीएम सूर्य योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने और पीएनजी गैस कनेक्शन व स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को अपनाने की अपील की।

वैशाली में सड़क पर शव रखकर हंगामा, हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

लोकतंत्र की शानः हाजीपुर। वैशाली जिले में लालगंज-हाजीपुर मुख्यमार्ग पर नामीडीह के पास आज सुबह यातायात बाधित हो गया। यह अवरोध एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत के विरोध में किया गया। जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना 15 मई 2026 को इसी मुख्यमार्ग पर नामीडीह के पास हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। मृतक की पहचान अमरजीत साह (35) के रूप में हुई है, जो लालगंज थाना क्षेत्र के बलुआ बसंता गांव निवासी रामप्रवेश साह के पुत्र थे। दुर्घटनास्थल काजीपुर थाथन थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी में था। अमरजीत अपने पांच भाई-बहनों में तीसरे स्थान पर थे और उनके दो बेटे तथा एक बेटी है। मृतक के परिजन विक्रम कुमार ने बताया कि अमरजीत साह हलवाई का काम करते थे। हाजीपुर से काम कर लौटने के दौरान काजीपुर में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। परिजनों को पुलिस द्वारा मौत की सूचना दी गई। आक्रोशित परिजनों ने तेज रफ्तार हाईवा चालकों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मार्ग पर हाईवा तेज गति से चलते हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

मिड-डे मील में बदबूदार अंडा मिलने पर हंगामा छात्रों, परिजन ने एनजीओ के खाने का विरोध किया

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड स्थित राष्ट्रीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरौल में मिड डे मील को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। विद्यालय में बच्चों के लिए भेजे गए भोजन और अंडे में बदबू आने की शिकायत पर ग्रामीण, अभिभावक और रसोइया आक्रोशित हो गए। विरोध के बाद बच्चों के बीच भोजन वितरण रोक दिया गया। ग्रामीणों ने एनजीओ के माध्यम से भेजे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए व्यवस्था बदलने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शुक्रवार को मिड डे मील में जो अंडे भेजे गए थे, उनमें से तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बच्चों को वह भोजन खिलाने से इनकार कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि एनजीओ के जरिए भेजे जाने वाले खाने की गुणवत्ता अक्सर खराब रहती है और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीण ममता कुमारी ने कहा कि बच्चों को स्कूल में अच्छी पढ़ाई और सुरक्षित भोजन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मिड डे मील स्कूल की स्थानीय रसोइयों द्वारा बनाया जाए तो खाना ताजा और बेहतर रहेगा। उन्होंने बताया कि कई बार खाने को लेकर शिकायतें मिली हैं और इस बार अंडे में से बदबू आ रही थी। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वे अपने बच्चों को घर से टिफिन देकर भेजेंगी, लेकिन खराब खाना नहीं खाने देंगी। वहीं ग्रामीण प्यारेलाल ने भी कहा कि बच्चों की ओर से अक्सर खाने की शिकायत की जाती है।

शादी के 16वें दिन कैश-ज्वेलरी लेकर दुल्हन फरार, दूल्हा बोला- साथ सोई थी, सुबह नींद खुली तो गायब मिली

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में शादी के 16 दिन बाद दुल्हन कैश और गहने लेकर फरार हो गई। घटना मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के लोमा गांव (वार्ड संख्या 1) की है। लोमा गांव के रामबाबू मांझी के बेटे धर्मेंद्र कुमार की शादी 25 अप्रैल को पियर थाना क्षेत्र की एक लड़की से हुई थी। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। शादी के 16वें दिन, जब धर्मेंद्र और उसके परिजन सो रहे थे, दुल्हन ने घर के बक्से और अलमारी में रखे 72 हजार रुपए नकद और लाखों के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। सुबह जब धर्मेंद्र की नींद खुली, तो उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर नहीं पाया। शुरुआती खोजबीन के बाद जब वह कहीं नहीं मिली, तो परिजनों को चिंता हुई। आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की गई, लेकिन दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिल सका। शक होने पर जब घर के कीमती सामानों की जांच की गई, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर से न केवल नकदी गायब थी, बल्कि शादी के गहने भी गायब थे। तब जाकर धर्मेंद्र और उसके पिता को एहसास हुआ कि वे एक सोची-समझी साजिश का शिकार हुए हैं और उनकी बहू असल में एक लुटेरी दुल्हन है।

सात निश्चय-3 की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन

सहरसा : सहरसा में आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "सात निश्चय-3" के तहत संचालित विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण को सुनिश्चित करना रहा। बैठक में "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के अंतर्गत 1000 प्रतिमाह प्राप्त करने वाली महिलाओं की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को दिया गया। साथ ही ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए हाट-बाजार विकसित करने पर भी चर्चा की गई। जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में आ रही समस्याओं—विशेषकर विद्युत कनेक्शन और कौशल विकास—पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मखाना की खेती एवं उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई प्रमंडल को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। कॉम्पफेड प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि लगभग 160 गांवों को छोड़कर शेष गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन हो चुका है, जबकि बाकी गांवों में भी शीघ्र गठन के निर्देश दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय स्थापित करने और जिला स्कूल, सहरसा तथा गर्ल्स हाई स्कूल सहित अन्य विद्यालयों को "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सदर अस्पताल परिसर में जल-जमाव की समस्या के शीघ्र समाधान के लिए सिविल सर्जन और नगर आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में नालों की उड़ाही और सफाई कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पर्यटन विकास के तहत मत्स्यगंधा परिसर, उग्रतारा मंदिर और मंडन मिश्र धाम के विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विद्यालयों में खेल मैदानों के विकास और हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने के निर्देश जिला खेल पदाधिकारी को दिए गए। साथ ही इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए विद्युत विभाग को सहयोग देने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण सड़कों के चरणबद्ध तरीके से दो लेन में चौड़ीकरण के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विराट रामायण मंदिर में नंदी की प्रतिमा होगी स्थापित

लोकतंत्र की शानः पटना

विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के पास साल के अंत तक नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिर में ग्राउंड लेवल तक काम पूरा हो गया है। अरघा भी इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंदी का निर्माण कराने के लिए आयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले कलाकार अरूण योगीराज से संपर्क किया गया है। एक सप्ताह के अंदर अरूण योगीराज विराट रामायण मंदिर का दौरा कर सकते हैं।

सावन में रूद्राभिषेक की होगी व्यवस्थाः इस बार यहां सावन में रूद्राभिषेक की भी व्यवस्था होगी। विराट रामायण मंदिर में रूद्राभिषेक के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। बुकिंग के अनुसार ही रूद्राभिषेक के लिए समय का स्लॉट मिलेगा। महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायण कुणाल ने निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा है। मंदिर का निर्माण करने वाली एजेंसी को कुल 46315.73 क्यूबिक मीटर निर्माण करना है, जिसमें अप्रैल 2026 तक 14135.10 क्यूबिक मीटर ही निर्माण कार्य हुआ है। अगर निर्माण एजेंसी द्वारा काम में तेजी नहीं लाई गई तो काम के लिए किसी और एजेंसी की भी मदद ली जा सकती है। मंदिर के बाऊंड्री के निर्माण कार्य के लिए टेंडर दिया जा चुका है। विराट रामायण मंदिर पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। श्री महावीर स्थान न्यास समिति द्वारा जानकीनगर (कैथवलिया) में 120 एकड़ में निर्माण हो रहा है।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों से 48 लाख मिले

- पटना में 40 लाख कैश-60 लाख की ज्वेलरी मिली

लोकतंत्र की शानः पटना

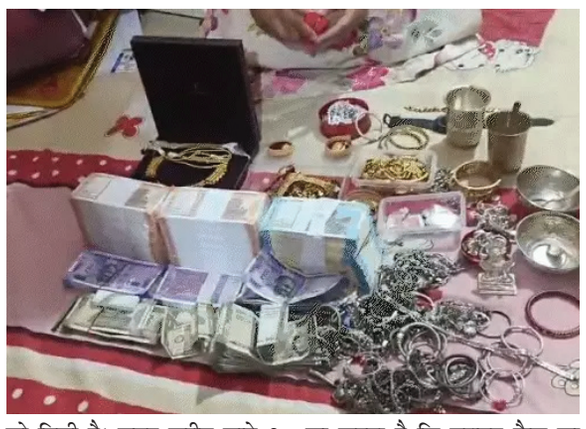

बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने रेड की। पटना और जमुई के 4 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई। पटना की मजिस्ट्रेट कॉलोनी के जगत विला अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर F-2 से 40 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये कैश डिजिटल लॉकर में रखे गए थे। 60 लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जमीन संबंधित कई लैंड डीड्स और निवेश के कागजात और बैंक अकाउंट्स की जानकारी EOU को मिली है। सुबह करीब साढ़े 8 बजे EOU के अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। जमुई में करीब 7 घंटे उनके आवास और ऑफिस को खंगाला गया। जमुई में रेड के दौरान 8 लाख कैश मिले हैं। साथ ही LIC में निवेश के कुछ पेपर मिले हैं। हालांकि, इंजीनियर गोपाल कुमार का कहना है कि बरामद कैश का उनके पास हिसाब है। गोपाल कुमार जमुई के झाझा में ग्रामीण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। EOU ने गोपाल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। वारंट के बाद ये एक्शन लिया गया है।

बिहार स्टेट ओपन ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह रहेंगी मौजूद

लोकतंत्र की शानः पटना

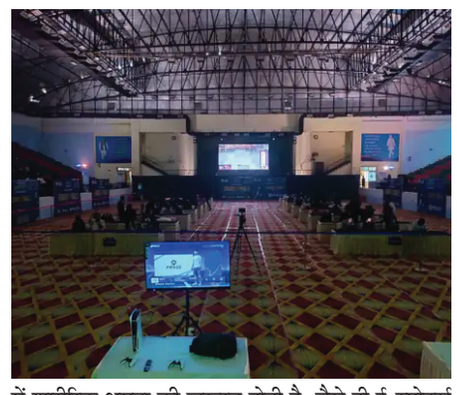

बिहार स्टेट ओपन ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आज ग्रैंड फिनाले है। पटना में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज विजेताओं को सम्मानित करेंगी। यह ई-स्पोर्ट्स का तीसरा संस्करण है, जिसका पूल प्राइज 5.75 लाख रुपए रखा गया है। इस ई-स्पोर्ट्स में पांच तरह के गेम में प्रतिभागी हिस्सा लिए हैं, जिसमें Chess.com, ई-फुटबॉल, EA FC- 26, BGMI और स्ट्रीट फाइटर- 6 जैसे गेम शामिल हैं। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा।

2182 प्रतिभागियों ने चैंपियनशिप के लिए किया रजिस्टरः इस प्रतियोगिता में कुल 2182 प्रतिभागियों ने रजिस्टर किया है। Chess.com में सबसे ज्यादा 1151 खिलाड़ी, ई-फुटबॉल में 223, EA FC-26 में 223, स्ट्रीट फाइटर- 6 में 35 और BGMI में 611 लोगों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसमें Chess.com, ई-फुटबॉल, EA FC- 26 के लिए 12 वर्ष से अधिक, BGMI और स्ट्रीट फाइटर- 6 के लिए 16 वर्ष के ऊपर की आयु निर्धारित की गई है।

क्या होता है ई-स्पोर्टसः ई-स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है। यह सिर्फ समय बिताने के लिए खेला जाने वाला वीडियो गेम नहीं है, बल्कि एक मानसिक और तकनीकी खेल है। जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है, वैसे ही ई-स्पोर्ट्स में एकाग्रता, क्विक रिफ्लेक्सेस और टीम रणनीति की आवश्यकता होती है। इसे अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति तक मान्यता मिल चुकी है। इस तरह ई-स्पोर्ट्स युवाओं के लिए एक कॅरियर विकल्प बन चुका है।

क्या हैं ई-स्पोर्ट्स के फायदे?: ई-स्पोटर्स के कई फायदे होते हैं। इसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाने से ऑनलाइन दुनियाभर के लोग एक प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। वैश्विक तौर पर आपको इसमें अपना करियर बनाने का लोगों को मौका मिलता है। इसमें खिलाड़ियों को आर्थिक तौर पर भी लाभ मिलता है। फिलहाल, इसमें नौकरी के भी अवसरों में काफी इजाफा हुआ है।

राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु "पंच परिवर्तन" की आवश्यकता : मुकुल कानिटकर

लोकतंत्र की शान

वैशालीः डॉ. सी. वी. रमण विश्वविद्यालय, वैशाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी काल के अंतर्गत आयोजित "प्रमुख जन संगोष्ठी" कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं प्रखर वक्ता श्री मुकुल कानिटकर जी, सदस्य, अखिल भारतीय प्रचार टोली ने राष्ट्र चेतना एवं सामाजिक जागरण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में लालगंज विधायक श्री संजय कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनका स्वागत विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. ब्रिजेश सिंह द्वारा किया गया। साथ ही सह विभाग संघ चालक, मुजफ्फरपुर श्री शंभूनाथ जी एवं जिला संघ चालक, वैशाली श्री नागेंद्र जी को भी मंच पर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री मुकुल कानिटकर जी ने कहा कि राष्ट्र की सशक्त चेतना का विकास समाज के सामूहिक प्रयास एवं सकारात्मक परिवर्तन से संभव है। इसी संदर्भ में उन्होंने "पंच परिवर्तन" की अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पहला परिवर्तन "कुटुंब प्रबोधन" का है, जिसे परिवारों में संवाद एवं संस्कार के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। दूसरा परिवर्तन "सामाजिक समरसता" का है, जिसका आधार परस्पर सम्मान एवं समान भाव है। तीसरा परिवर्तन राष्ट्रहित में संयम एवं अनुशासन का है। चौथा परिवर्तन "पर्यावरण प्रेम" का है, जिसे मानवीय संवेदनाओं एवं प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व के माध्यम से अपनाया जा सकता है। वहीं पाँचवाँ परिवर्तन "स्वबोध" का है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने राष्ट्र, संस्कृति एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनता है। उन्होंने कहा कि इन पाँच मूल परिवर्तनों को घर-घर तक पहुँचाने एवं जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इन्हीं के माध्यम से राष्ट्र की राष्ट्रीय चेतना और अधिक सशक्त एवं विकसित होगी। अपने उद्बोधन के उपरांत श्री कानिटकर जी ने उपस्थित श्रोताओं एवं विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया तथा विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. बसंत सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों, शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्र चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिवार, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

किशनगंज में 4 पेट्रोल पंप बंद, बंगाल जा रहे लोग

लोकतंत्र की शानः पटना

- पेट्रोल-डीजल के दाम 3 रुपए/लीटर बढ़ने से और हो रही परेशानी

अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग के बीच देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। 15 मई से नए दाम लागू हो गए हैं। बिहार में अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। गुरुवार तक पटना में पेट्रोल की कीमत 105.37 रुपए प्रति लीटर थी।

वहीं डीजल के दाम भी बढ़े हैं अब पटना में डीजल की कीमत 94.65 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि कल तक डीजल की कीमत 91.65 रुपए प्रति लीटर थी।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में CNG भी 2 प्रति किलो तक महंगी हो गई हैं। किशनगंज में 4 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। इससे लोग बंगाल जाकर गाड़ियों में तेल भरवा रहे हैं। इधर, गयाजी में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई। यहां पेट्रोल-डीजल लेने वाले वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तैनात की गई थी।

प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजेश कुमार के स्थानांतरण पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन

सहरसा : श्री राजेश कुमार, भा०प्र०से०, प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के स्थानांतरण के उपरांत आज दिनांक 16.05.2026 को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। समारोह के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने श्री राजेश कुमार के कार्यकाल को स्मरण करते हुए उनके कुशल नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता तथा जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में कोशी प्रमंडल में कई महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं लोकहितकारी कार्यों को गति मिली, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सह अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री संजीव कुमार चौधरी, आर०डी०डी०ई० श्री अमित कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री राजेश कुमार के साथ कार्य करने के अनुभव साझा किए। सभी ने उनके सरल स्वभाव, निर्णय क्षमता तथा टीम के साथ समन्वय स्थापित करने की उनकी विशेष योग्यता की सराहना की। वक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि श्री राजेश कुमार ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक पारदर्शिता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तथा जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी, जिससे आम जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति और अधिक सुदृढ़ हुआ। उनके नेतृत्व में कई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ, जो लंबे समय तक क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। समारोह के अंत में सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री राजेश कुमार के उज्ज्वल भविष्य एवं भावी कार्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। साथ ही, उनके योगदान को सदैव स्मरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की गई।

सहरसा में एलपीजी गैस की आपूर्ति सामान्य, प्रशासन की सख्त निगरानी जारी

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन

सहरसाः जिला प्रशासन, सहरसा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले में घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रित है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रमुख गैस कंपनियों—इण्डेन (Indane), एचपी गैस (HP Gas) एवं भारत गैस (Bharatgas)—के पास पर्याप्त मात्रा में भरे हुए सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है तथा आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से संचालित हो रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक बुकिंग (पैनिक बुकिंग) से बचें। सभी गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक समयबद्ध तरीके से रिफिल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

इण्डेन गैस की स्थितिः- जिले में इण्डेन गैस के वितरकों के पास वर्तमान में 2,890 सिलेंडरों का भरा हुआ स्टॉक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 2,580 सिलेंडर आपूर्ति में हैं, जिससे कुल उपलब्धता 5,470 सिलेंडरों तक पहुंच जाती है। हाल के दिनों में 2,108 सिलेंडरों की सफल डिलीवरी की गई है और लंबित बुकिंग को औसतन 4 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

एचपी गैस की स्थितिः- एचपी गैस वितरकों के पास 4,176 सिलेंडरों का ओपनिंग स्टॉक था, जिसमें 1,948 सिलेंडरों की नई खेप शामिल होने के बाद कुल स्टॉक 6,124 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,512 सिलेंडरों की सफल होम डिलीवरी की गई है।

भारत गैस की स्थितिः- भारत गैस वितरकों के पास 2,815 सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसमें 1,975 ओपनिंग स्टॉक एवं 840 ट्रांजिट सिलेंडर शामिल हैं। प्रतिदिन लगभग 1,101 सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है तथा बैकलॉग औसतन 2.3 दिनों का है, जो स्थिति के सामान्य होने का संकेत है।

प्रशासन के सख्त निर्देशः- जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को सघन मॉनिटरिंग एवं औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं, ताकि कालाबाजारी या निर्धारित दर से अधिक वसूली पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। जिन गैस एजेंसियों में पेंडिंग बुकिंग अधिक है, उन्हें अतिरिक्त वाहन एवं मानव संसाधन लगाकर डिलीवरी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी वितरकों को अपने नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन स्टॉक की स्थिति एवं बुकिंग क्रमांक प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि सहरसा जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ है और किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर आज सीधी आएंगे

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर 17 मई को दोपहर पश्चात मऊगंज होते हुए 1:15 पर सीधी की सीमा कमर्जी तुर्रा पहाड़ से प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष टेलर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ पटपरा तालाब, स्थानीय सम्राट चौक, अस्पताल चौक, विकास भवन में विशेष रूप से पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, उसके पश्चात शायं काल 3 बजे स्थानीय मानस वन सीधी में युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा कंपू ने विभिन्न स्थानों पर शानदार स्वागत की तैयारियो का जायजा लिया और युवाओं से स्थानीय मानस भवन में पहुंचकर युवा सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है।

बुंदेलखंड की सड़कों पर "भ्रष्टाचार का डामर" ?

» इंजीनियर आशीष भारती पर गंभीर आरोप, सरकार की मंशा को खुली चुनौती!

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर ,कटनी, मध्य प्रदेश, सागर/छतरपुर। प्रदेश में डॉक्टर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जहां विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही की बात कर रही है, बाखुदी अच्छा कार्य कर रही है मगर वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि विभागीय इंजीनियर आशीष भारती की कार्यशैली ने शासन की मंशा पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी अनुसार, छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों में जिन सड़कों का निर्माण आशीष भारती की निगरानी में हुआ, उनमें गुणवत्ता मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़कें समय से पहले उखड़ रही हैं, जबकि आम जनता धूल, गड्ढों और बदहाल यातायात से परेशान है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर आशीष भारती का विभाग में इतना रसूख है कि संभागीय स्तर के अधिकारी भी उसके खिलाफ बोलने से बचते हैं। आरोप यह भी हैं कि वह खुलेआम कहता है कि "काम नियम और मानकों से नहीं, मेरे हिसाब से होगा।" यही वजह है कि सड़क निर्माण से जुड़ी कई शिकायतें विभागीय फाइलों में दबकर रह गईं। सूत्र यह भी बताते हैं कि आशीष भारती लंबे समय से मनचाहे पदों पर जमे हुए हैं और विभागीय जांच के बावजूद प्रभावशाली संरक्षण के चलते कार्रवाई से बचे हुए हैं। वर्तमान में सागर से अटैचमेंट होने के बावजूद छतरपुर क्षेत्र के विकास कार्यों में उनका हस्तक्षेप लगातार बना हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर साइकिल से निकले चेयरमैन कौसर अब्बास, निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

लोकतंत्र की शान , सम्भल/सिरसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल-डीजल बचत एवं पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को गंभीरता से लेते हुए सिरसी नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास ने शुक्रवार को भीषण गर्मी के बीच साइकिल से नगर भ्रमण कर एक अलग मिसाल पेश की। चेयरमैन के इस सादगी भरे अंदाज को देखकर नगरवासियों ने उनकी जमकर सराहना की। चेयरमैन कौसर अब्बास ने नगर की विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों का साइकिल से पहुंचकर निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद ठेकेदारों को गुणवत्ता पूर्ण कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पंचायत की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने राहगीरों व स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अचानक दोपहर की तेज गर्मी में चेयरमैन को साइकिल चलाते देख लोग हैरान रह गए। नगरवासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच इसी तरह सादगी और जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। चेयरमैन कौसर अब्बास ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि प्रत्येक नागरिक छोटे-छोटे प्रयास करे तो देश को ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी सफलता मिल सकती है।उनके इस अनोखे और जनहितकारी कदम की नगर में पूरे दिन चर्चा होती रही।

महिला की सुरक्षा सम्मान एवं सहायता के लिए जनपद के समस्त पुलिस थानों में महिला सुरक्षा को मन चलो पर कार्रवाई करते हुए

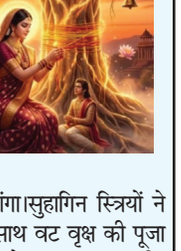

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, मंडल मुरादाबाद/उत्तर प्रदेश/जिला अमरोहा पुलिस कप्तान लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों हुए हुए मनचले के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस कप्तान अखिलेश भदोरिया के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्र अधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक हसनपुर राजीव कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना हसनपुर पुलिस एस आई विजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल रामदेव हेड कांस्टेबल दिलशेर आज सुबह के टाइम एंटी रोमियो के तहत महिलाओं की सुरक्षा सम्मान एवं सहायता के लिए जनपद के समस्त पुलिस थानों में महिला संबंधित शिकायतों की तकरीर सनी प्रश्नों में जानकारी एवं हर संभव सहायता प्राप्त कराई जाती है इसी के तहत एंटी रोमियो की कार्यवाही करते हुए जीजीआईसी इंटर कॉलेज के पास म मन चलो को चेकिंग करते हुए हेड कांस्टेबल रामदेव ने अपनी सराहना कार्य किया और म न चलो पर कार्यवाही की

सुहागिन महिलाओं ने विधि-विधान के साथ की वट सावित्री की पूजा

पति की लंबी उम्र की कामना की

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा,अमरोहा/ हसनपुर= शनिवार को सुहागिनों ने पति की लंबी आयु की कामना कर व्रत रखकर वटवृक्ष की पूजा कर कलावा बांधा। हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए कई व्रत रखती हैं। इनमें एक प्रमुख व्रत वट सावित्री व्रत भी है। आपको बता दें कि शहर अमरोहा/ हसनपुर सहित क्षेत्र के विभिन्न भागो में शनिवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजा विधि विधान के साथ की। इस अवसर पर महिलाओं ने वटवृक्ष के नीचे फल फूल और पूजन सामग्री के साथ पूजन अर्चन किया। कच्चे धागे के साथ वृक्ष की परिक्रमा किया और अपने पति के दीर्घायु होने का वरदान मांगा।सुहागिन स्त्रियों ने सोलह श्रृंगार कर पति की लंबी आयु की कामना के साथ वट वृक्ष की पूजा की। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा समापन के पश्चात सभी महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन अर्चन किया। श्रीमती नीता महेश्वरी ने बताया कि वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं और मां सावित्री की विधि-विधान से पूजा करती हैं। यह पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष तथा देवी सावित्री की पूजा करती हैं। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। इसके लिए व्रत वाले दिन पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री होना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

चुरहट में बनी घटिया नाली की जांच करने पहुंची चार सदस्यीय टीम

» कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद थोड़ा सख्त हुआ प्रशासन चार सदस्यीय टीम गठित

» भ्रष्टाचार के पनाहगाह उपयंत्री पर हो सकती है कार्यवाही

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के नगर परिषद चुरहट में घटिया निर्माण की पोल खुलने के बाद कोहराम मचा हुआ है, एक तरफ संबंधित उपयंत्री को सीएमओ द्वारा नोटिस भेज कर जहां जवाब तलब किया गया है, वहीं उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर चार सदस्यीय टीम द्वारा मौके से पहुंच कर जांच शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय हैं कि चुरहट नगर परिषद अंतर्गत चल रहे घटिया निर्माण कार्यों को लेकर उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय एवं समाजसेवी प्रदीप सिंह द्वारा लगातार स्थानीय प्रशासन को जहां अवगत कराया जा रहा था वहीं इस बात को सार्वजनिक करने के लिए सोशल मीडिया में शेयर किया जाता रहा, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त उपयंत्री को इनकी शिकायतो का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, अब जब कलेक्टर विकास मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू करा दी तो उनके परिजन भी सोशल मीडिया में सफाई देने लगे हैं। हालांकि शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम ने बीछी रोड चुरहट में नगर परिषद् द्वारा निर्मित घटिया नाली क्षतिग्रस्त होने एवं वार्ड क्रमांक-14 नगर परिषद् चुरहट अंतर्गत निर्माणाधीन / निर्मित नाली में गंभीर गुणवत्ता विहीन निर्माण की जांच शुरू कर दी है। मजे की बात यह है घटिया निर्माण कार्य की पोल खुलने पर उपयंत्री ने संविदाकार से सांठगांठ कर ध्वस्त हुई निर्माणाधीन नाली की सच्चाई छिपाने के लिए रात में ही रंगरोदन शुरू करा दिया था। रात में निर्माण कार्य कराने से यह भी साफ हो गया है कि उपयंत्री अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

प्रयोगशाला भेजा गया सैंपल

घटिया निर्माण कार्य की जांच करने पहुंची संयुक्त टीम ने मौके पर उपलब्ध मटेरियल एवं निर्माण कार्य में लगे मटेरियल की सैंपलिंग कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जांच टीम द्वारा मौके पर की गई जांच का प्रतिवेदन प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद ही सौंपी जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद ने गंभीरता दिखाते हुए शिकायत के आधार पर 07 मई को कलेक्टर डूडा को पत्र लिखकर जांच कराने के बात रखी थी, एसडीएम के पत्र पर कलेक्टर डूडा ने एसडीएम के ही नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम गठित की है। मौके पर पहुंची जांच टीम की जानकारी मिलते ही समूचे नगर परिषद चुरहट में हड़कंप मच गया है।

टीम में इन्हें किया गया है शामिल

नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय एवं समाजसेवी प्रदीप सिंह की शिकायत पर एसडीएम द्वारा कलेक्टर डूडा को लिखे गए पत्र में टेक्निकल अधिकारियों से जांच कराने की मांग उठाई थी, जिस पर कलेक्टर डूडा ने एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद के नेतृत्व में साक्षी गौतम तहसीलदार चुरहट के साथ साथ कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी को शामिल किया गया है। उक्त टीम द्वारा चुरहट नगर परिषद में कराए गए घटिया निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इसके पूर्व घटिया निर्माण कार्य उजागर होने पर चुरहट नगर परिषद सीएमओ ने भी उपयंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा था। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि अगर ईमानदारी पूर्वक कार्यवाही की गई तो उपयंत्री एवं संबंधित संविदाकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना तय है।

इनका कहना है। कलेक्टर के निर्देश पर निर्माण कार्य की जांच शुरू कर दी गई है, टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य में उपयोग किए गए मटेरियल का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही होगी।

विकास कुमार आनंद, एसडीएम चुरहट।

कृषि रथ को हरी झंडी, अब ई-टोकन से मिलेगी किसानों को खाद

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर शासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर सीधी महोत्सव के निर्देशानुसार शनिवार 16 मई 2026 को जनपद क्षेत्र कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवार से कृषि विभाग द्वारा कृषि जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत भगवार की सरपंच श्रीमती चेतना सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया और किसानों के लिए सफल एवं समृद्ध खरीफ सीजन की मंगलकामना की। शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे रवाना हुए इस कृषि रथ का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव पहुंचकर किसानों को शासन की महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की जानकारी देना है। रथ के माध्यम से किसानों को विशेष रूप से ई-टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली 2010, निंदाई प्रबंधन, खरीफ फसल की तैयारी, उन्नत खेती तकनीक एवं खाद वितरण व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रगतिशील कृषक संतोष गर्ग, दामतिया बाई, अनिल सिंह, कृषि विभाग कुसमी के वरिष्ठ एईडी एस.पी. साकेत, कु. हिमाशी सिंह, कु. सोनाली वर्मा, त्रिवेणी मुकाती तथा मेध सिंह मेढ़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस बार किसानों को खाद वितरण ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होगा और लंबी-लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। विभाग का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही कृषि विभाग कुसमी के अधिकारी एस.पी. साकेत ने बताया कि कृषि रथ लगातार गांवों में भ्रमण कर किसानों को खरीफ सीजन से पहले जागरूक करेगा। शासन की मंशा है कि हर किसान तक योजनाओं की सही जानकारी पहुंचे और आधुनिक तकनीक का लाभ सीधे खेत तक पहुंचे। कृषि विभाग का यह अभियान क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अधिमास की तैयारी में मंदिर प्रबंधन,सजकर तैयार है देवालय

» बढ़ौरा शिव मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारी का जिला प्रशासन ने लिया जायजा, व्यवस्था बनाने के दिये शख्त निर्देश

» अधिमास का शुभारंभ कल से, शिव मंदिरों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़

» बढ़ौरा शिव मंदिर में मेले की सुरक्षा एवं सुविधाओं का प्रशासन ने लिया जायजा

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक प्रसिद्ध बढ़ौरा में अधिमास मेला इस वर्ष 17 मई 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। शनिवार को ग्राम पंचायत बढ़ौरा में आयोजित तैयारियों की समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण कार्यक्रम में नायब तहसीलदार गोपद बनास एकता शुक्ला एवं सेमरिया थाना प्रभारी केदार परौहा ने मेले में पुलिस बल की तैनाती, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं नायब तहसीलदार एकता शुक्ला ने संबंधित विभागों को समय रहते सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर ली जाएंगी। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और जनसमूह की विशाल सहभागिता का केंद्र बनने वाला बढ़ौरा मलमास मेला एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। पर आयोजित होता है। पूरे एक माह तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। थाना प्रभारी केदार परौहा ने मेले में पुलिस बल की तैनाती, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं नायब तहसीलदार एकता शुक्ला ने संबंधित विभागों को समय रहते सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर ली जाएंगी। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और जनसमूह की विशाल सहभागिता का केंद्र बनने वाला बढ़ौरा मलमास मेला एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बनने जा रहा है।

कटनी महिला कांग्रेस प्रभारी का कटनी आगमन

लोकतंत्र किस शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। गत दिनो महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी श्रीमती विजयलक्ष्मी मिश्रा जी का कटनी में प्रथम आगमन हुआ जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन एवं सदस्यता की जानकारी ली एवं आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की, महिला कांग्रेस प्रभारी विजय लक्ष्मी मिश्रा जी ने बताया कि संगठन को मजबूती देने एवं संगठन के विस्तार हेतु उन्हें कटनी महिला कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इसके लिए उन्होंने महिला कांग्रेस की समस्त पदाधिकारी नवनियुक्त प्रकोष्ठ अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए संगठन के विस्तार के लिए सुझाव दिए। कटनी महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रजनी वर्मा ने बताया की प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों मैं संगठन की मजबूती हेतु जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में जाकर उन क्षेत्रों की महिला कांग्रेस को एकजुट करके संगठन को मजबूती एवं विस्तार देने का कार्य करेंगी, साथ महिला कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाकर महिला कांग्रेस में महिलाओं को मजबूत बनाने एवं नए सदस्यों को जोड़ने में मदद करेंगी महिला कांग्रेस प्रभारी विजयलक्ष्मी मिश्रा जी की उपस्थिति में प्रदेश महासचिव रजनी वर्मा जी के नेतृत्व में पेट्रोल,डीजल,सी एन जी, एवं दूध के बड़े हुए दामों को लेकर बरगवां स्थित पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया जिसमें महिला कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने का आवाहन किया गया, प्रदेश महासचिव रजनी वर्मा ने कहा कि यदि सरकार इन बड़े हुए दामों को वापस लेकर महंगाई कम नहीं करेगी तो जल्दी ही पूरी महिला कांग्रेस जनता के साथ सड़कों पर सरकार का विरोध प्रदर्शन करेगी दिन प्रतिदिन बढ़ते दामों ने महिलाओं की पूरी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और आम जनता की महंगाई से कमर तोड़ दी है इसके विरोध में पूरी महिला कांग्रेस पीड़ित जनता के साथ खड़ी है, साथ ही महिला प्रभारी विजय लक्ष्मी मिश्रा शहर जिला अध्यक्ष अमित शुक्ला एवं पूर्व प्रदेश महासचिव ,प्रियदर्शन गौर जीने भी इस तरह लगातार पेट्रोल डीजल cng के बढ़ते हुए दामों के विरोध में अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे भाजपा सरकार की नाकामी बताया।। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित शुक्ला, पूर्व प्रदेश महासचिव प्रियदर्शन गौर, उपभोक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला,माधुरी जैन आदिता वर्मा, कल्पना पाठक, गीता निषाद,आकांक्षा मिश्रा, मीना पटेल, रूपा पाठक,सुमन सैनी, दुर्गावती कोल,सौम्या रांधेलिया,मीनाक्षी बलवी , हेमा शर्मा,नीरा, राजेश जाटव, अंकिता सिंह, लक्ष्मी सिंह दिग्विजय सिंह, आफताब अहमद, अभिषेक शिवहरे, रमेश अहिरवार, दिलदार खान, हर्षित मिश्रा, कौशल मिश्रा, मुन्ना कुशवाहा, अजय गोटिया, मुकेश परोहा, मंगल सिंह, मंगल चौधरी , कमला पांडे, सरस्वती शर्मा आदि कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही।

पाइनवुड विद्यालय में राज्य स्तरीय एंटी-डोपिंग पोषण जागरुकता कार्यशाला

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

सहरनपुरः पाइनवुड विद्यालय में "राज्य स्तरीय एंटी-डोपिंग एवं पोषण जागरूकता कार्यशाला" का आयोजन किया गया इस कार्यशाला का आयोजन फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PEFI) द्वारा किया गया , जो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA), भारत तथा पाइनवुड स्कूल के सहयोग से आयोजित किया गया ।आज की इस कार्यशाला का आयोजन नैतिक खेल भावना, डोपिंग के हानिकारक प्रभावों तथा स्वस्थ, अनुशासित और सफल खेल संस्कृति के निर्माण में उचित पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया ।आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में फिटनेस, पोषण और निष्पक्ष खेल भावना के प्रति जागरूकता केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक युवा के लिए आवश्यक है, जो एक स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जीने की आकांक्षा रखता है। इस कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यातिथि डॉ. पीयूष जैन

सेमरिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में पटाखा व विस्फोटक सामग्री जब्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। जिले में जनसुरक्षा को ल

`कर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विकास मिश्रा के निर्देशन में जिलेभर में पटाखा भंडारण केंद्रों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सेमरिया में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से रखी भारी मात्रा में पटाखा एवं विस्फोटक सामग्री जब्त की। नायब तहसीलदार एकता शुक्ला के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में जांच के दौरान पाया गया कि लाइसेंस प्राप्त गोदाम के बजाय मुख्य बाजार स्थित दुकान और घर में विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था, जिससे जन-धन की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। टीम ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कर सामग्री को सील कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों और लाइसेंस नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध भंडारण या नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अब ATVM से टिकट निकालना हुआ और भी आसान : UPI भुगतान से यात्री स्वयं प्राप्त कर सकेंगे टिकट

लोकतंत्र कि हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्यप्रदेश

» स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं, QR स्कैन कर मिनटों में मिलेगा अनारक्षित टिकट

जबलपुर। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल द्वारा ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) के माध्यम से टिकट निकालने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सहज बनाया गया है। अब यात्री बिना किसी स्मार्ट कार्ड के, केवल मोबाइल (UPI) भुगतान के माध्यम से स्वयं अपना टिकट निकाल सकते हैं। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करना तथा समय की बचत सुनिश्चित करना है। ATVM मशीनों के माध्यम से अनारक्षित टिकट अब कुछ ही मिनटों में आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

ATVM से टिकट निकालने की सरल प्रक्रिया:-यात्री निम्नलिखित आसान चरणों का पालन कर ATVM से टिकट प्राप्त कर सकते हैं—

- ATVM स्क्रीन पर उपलब्ध "अन्य स्टेशन" विकल्प पर क्लिक करें।
- कीबोर्ड के माध्यम से स्टेशन का नाम टाइप करें एवं स्टेशन का चयन करें।
- यात्रा का विवरण भरें एवं भुगतान विकल्प पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन कर UPI के माध्यम से भुगतान करें। भुगतान पूर्ण होते ही मशीन से टिकट प्राप्त करें।

बिना किसी सहायता के स्वयं टिकट निकालें-रेलवे प्रशासन स्पष्ट करता है कि यदि ATVM मशीन पर कोई फैसिलिटेटर/कर्मचारी तैनात हो, तब भी यात्री बिना उनकी सहायता के स्वयं अपना टिकट निकाल सकते हैं। यात्रियों को स्वावलंबी बनाना तथा डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देना रेलवे की प्राथमिकता है।

शिकायत हेतु व्यवस्था-यदि ATVM मशीन से स्वयं टिकट बनाने के दौरान किसी यात्री को अनावश्यक रूप से रोका जाता है अथवा असुविधा होती है, तो यात्री इसकी शिकायत बुकिंग पर्यवेक्षक या उप स्टेशन प्रबंधक से कर सकते हैं। रेलवे द्वारा ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

रेलव की अपील-जबलपुर रेल मंडल यात्रियों से अपील करता है कि वे ATVM मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, डिजिटल भुगतान को अपनाएं तथा सुगम, सुरक्षित एवं तेज़ टिकटिंग व्यवस्था का लाभ उठाएं।

संक्षिप्त समाचार

मालदीव में इटली के 5 गोताखोरों की मौत, समुद्र के नीचे गहरी गुफाओं की खोज में निकले थे, सिर्फ एक का शव मिला

माले। मालदीव के वावू एटोल में इटली के 5 गोताखोरों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा डाइविंग हादसा बताया है। सभी डाइवर्स 50 मीटर गहराई में मौजूद गुफाओं की खोज के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब तक सिर्फ एक शव बरामद हुआ है। खराब मौसम और समुद्र की कठिन परिस्थितियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक बाकी चार डाइवर्स के शव अब भी गुफा के अंदर होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन शनिवार को फिर शुरू किया जाएगा। मालदीव सरकार ने मृतकों की पहचान मोनिका मोंटेफाल्कोने, जॉर्जिया सोमाकाल, फेडेरिको गुआल्टिएरी, म्यूरियल ओडेनिनो और जियानलुका बेनेडेट्टी के रूप में की है। यह टीम 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' नाम की बोट से समुद्र में गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच में से कम से कम चार डाइवर्स इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा से जुड़े थे। जियानलुका बेनेडेट्टी यॉट पर बोट ऑपरेशंस मैनेजर थे। उनका शव ही अब तक बरामद किया जा सका है। मोनिका मोंटेफाल्कोने मरीन बायोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा में ट्रॉपिकल मरीन इकोलॉजी और अंडरवॉटर साइंस की प्रोफेसर थीं। इटली की मीडिया के मुताबिक वह मालदीव में एक आइलैंड मॉनिटरिंग कैंपेन की साइंटिफिक डायरेक्टर भी थीं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी बेटी जॉर्जिया सोमाकाल को भी समुद्र और डाइविंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 31 साल की म्यूरियल ओडेनिनो मरीन बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट थीं। उन्होंने कई वैज्ञानिक रिसर्च पेपर भी लिखे थे। वहीं, 31 साल के फेडेरिको गुआल्टिएरी ने हाल ही में मरीन बायोलॉजी और इकोलॉजी में डिग्री पूरी की थी। वह सर्टिफाइड स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी थे। बेनेडेट्टी पहले बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम करते थे। बाद में उन्होंने डाइविंग के शौक के चलते 2017 में मालदीव शिफ्ट होने का फैसला किया और बोट ऑपरेशंस मैनेजर बन गए।

नेपाल में 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी पर रोक

काठमांडू। नेपाल-भारत सीमा नाकों पर दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जा रहे कस्टम शुल्क पर नेपाल उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार शुल्क लगाने संबंधी वित्त मंत्रालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपभोग के सामान लाने पर भंसार शुल्क लगाने की व्यवस्था को व्यापार संधि के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए अधिवक्ता अमितेश पण्डित सहित अन्य लोगों ने रिट याचिका दायर की थी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार कर अनिवार्य करने का निर्णय लिया था। इसके बाद तराई-मधेश क्षेत्र के सीमा नाकों पर सख्ती शुरू कर दी गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। 27 अप्रैल को दायर रिट याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को अंतरिम आदेश पर बहस के लिए बुलाया था। सरकार की ओर से दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अदालत ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कस्टम विभाग के नाम अंतरिम आदेश जारी करते हुए तत्काल इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में सरकार बनने के तुरंत बाद सीमा नाकों पर सख्ती शुरू की गई थी। सीमा पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा सामान जब्त किए जाने के फोटो और वीडियो सार्वजनिक होने के बाद व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन सरकार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में हनुमान-चालीसा पाठ हुआ, मां वाग्देवी की पूजा हुई

धार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार स्थित विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को राजा भोज के समय का वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। फैसले के बाद शनिवार सुबह श्रद्धालुओं और अलग-अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में भोजशाला पहुंचकर दर्शन और पूजा-अर्चना की। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के ASI आदेश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है। इस आदेश में मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को तय अवधि के लिए नमाज की अनुमति दी गई थी। शनिवार सुबह सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी परिसर पहुंचे। इनमें संरक्षक विश्वास पांडे, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा, श्रीश दुबे, केशव शर्मा और अशोक जैन शामिल थे। सभी ने मां वाग्देवी के स्थान और यज्ञ कुंड के पास पुष्प अर्पित कर दंडवत प्रणाम किया। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने कहा कि सालों बाद उन्हें बिना रोक-टोक पूजा करने का अवसर मिला है। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा, "भोजशाला का कण-कण यह दर्शाता है कि यह एक मंदिर है।" मुस्लिम पक्ष की आगे की कानूनी कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन भोजशाला मंदिर था, मंदिर है और हमेशा मंदिर ही रहेगा। फिलहाल पूरे धार शहर और भोजशाला परिसर की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में 28 दिनों में 733 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में पिछले 28 दिनों में ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े 733 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपी ड्रग पेडलर्स के 47 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए 373 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए और नियमों का उल्लंघन करने पर 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी खत्म करने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया था। तस्करों से जुड़े 180 आधार कार्ड डिएक्टिवेट (निष्क्रिय) कर दिए गए। इसके साथ ही सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे नशीली दवाओं से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी सामने आकर दें। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ में करीब 93 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत जम्मू के बाग-ए-बाहु थाना में दर्ज एक मामले से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक यह मामला 14 जनवरी 2026 का है। उस दिन जम्मू के नरवाल स्थित राजीव नगर निवासी अरुण सिंह को नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 5.61 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इसके बाद NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

भारत में 24 घंटे काम करने वाली न्याय व्यवस्था की जरूरत

एजेंसी, जबलपुर

भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पैरालीगल वालंटियर्स तैयार किए जाने चाहिए, जो लोगों को डिजिटल न्याय प्रणाली से जोड़ सकें। यह बातें देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में कहीं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफार्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के साथ केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। इससे पूर्व नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्चरल एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर में आयोजित सेमिनार में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफार्म इंटीग्रेशन" का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एनुअल रिपोर्ट : 2025 का भी विमोचन किया गया।

छोटे डिजिटल कदम भविष्य में बनेंगे बड़ी क्रांतिः मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नर्मदा नदी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अमरकंटक से निकलने वाली छोटी धारा आगे चलकर विशाल स्वरूप ले लेती है, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था में किए जा रहे छोटे-छोटे तकनीकी सुधार आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस थाना, फॉरेंसिक लैब, मेडिकल सिस्टम, लीगल सेल, अदालत और जेल से संबंधित सूचनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसे अनूठी पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में इस मॉडल को देशभर में लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

एआई के जरिए लंबित मामलों के समाधान पर कामः न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर एक विशेष कमेटी गठित की गई है। यह समिति लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और प्रक्रियाओं को अधिक सक्षम बनाने के उपायों पर काम कर रही है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में इस संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका तकनीक अपनाने के मामले में पहले से अग्रणी रही है।

पंजाब- बोरवेल से 9 घंटे बाद निकाला बच्चा

एजेंसी, जालंधर/होशियारपुर

- बाहर आते ही मां से लिपटकर रोया, खेलते समय गिरा, 30 फीट नीचे फंसा था

पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को करीब 9 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद बच्चा अपनी मां से लिपटकर रोया। NDRF, SDRF, पंजाब पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के सहयोग से यह ऑपरेशन सफल बना। खेलते हुए बोरवेल में गिरा बच्चा करीब 30 फीट नीचे फंसा था। उसे शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 12:40 बजे बोरवेल से बाहर निकाला और तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसी हालत खतरे से बाहर बताई गई।

DC आशिका जैन और SSP संदीप कुमार मलिक ने ऑपरेशन का शुरुआत से नेतृत्व किया। बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद DC ने बताया कि बच्चे को बचाने के बाद एंबुलेंस में डॉक्टरी टीम के साथ आगे की जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उसका इलाज चल रहा है।

सिलसिलेवार जानिए पूरा मामला...: 15 दिन से खोदा जा रहा था बोरवेलः DC ने बताया कि शाम करीब 4 बजे होशियारपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती गांव चक्क समाना में यह घटना हुई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। मजदूर हरिंदर और आशा का बेटा गुरकरन सिंह अपने घर के बगल में खुले बोरवेल में गिर गया था। यह बोरवेल करीब 15 दिन से खोदा जा रहा था।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर असम पुलिस और बीएसएफ ने 14 घुसपैठियों को रोका

एजेंसी, गुवाहाटी

असम में नई सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। असम पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त अभियान चलाकर 14 कथित घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सीमा पर तैनात जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं और घुसपैठ की हर कोशिश को विफल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम पुलिस और बीएसएफ के सतर्क जवानों ने 14 घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। मुख्यमंत्री ने जवानों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि, इससे एक दिन पहले 14 मई को भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि असम पुलिस और बीएसएफ ने 12 कथित घुसपैठियों को असम में प्रवेश करने से पहले ही पकड़कर उनकी कोशिश नाकाम कर दी थी।

वोटर लिस्ट मामले में सुनवाई टली, याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी पर लगाया देरी कराने का आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट मामले में सुनवाई टलने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने उन पर जानबूझकर सुनवाई में देरी कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के वकील समय कम होने का हवाला देकर बार-बार बहस टाल रहे हैं, जिससे मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है। अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें निर्वाचन आयोग से प्राप्त दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था और सभी दस्तावेज अदालत में जमा कर दिए गए हैं। इसके बावजूद विपक्ष की ओर से बहस नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर "तारीख पर तारीख" ली जा रही है।

उन्होंने कहा कि आज भी सोनिया गांधी के वकील अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अब मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है। विकास त्रिपाठी ने कहा कि पहले भी विपक्ष की ओर से बहस टलती रही है। उन्होंने कहा कि वह अदालत में उपस्थित हैं और आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर से बहस नहीं की जा रही है। उन्होंने इसे सुनवाई में देरी करने की रणनीति करार दिया।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का कथित रूप से नाम जुड़वाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर शनिवार को सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की है। याचिकाकर्ता की ओर से निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी। इससे पहले 18 अप्रैल को अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज किए जाने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। 9 दिसंबर 2025 को अदालत ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन अप्रैल 1983 में दिया था। ऐसे में 1980 में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया होगा, जो एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। याचिका में अदालत से सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार का मितव्ययिता आदेश जारी, विदेश यात्राओं पर रोक और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा

एजेंसी, रायपुर

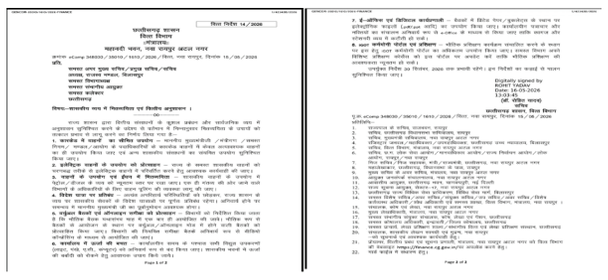

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मितव्ययिता संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव के जारी इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन स्थापित करना है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इन निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारियों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। अन्य शासकीय संसाधनों का भी संयमित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य के शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ईंधन व्यय में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के व्यय पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल एवं ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्देशों के अनुसार भौतिक बैठकें यथासंभव माह में एक बार ही आयोजित की जाएंगी और विभागीय समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होंगी। कार्यालयीन समय के बाद सभी विद्युत उपकरण—जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर—अनिवार्य रूप से बंद किए जाएंगे। शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। बैठकों में मुद्रित दस्तावेजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलों (पीडीएफ, पीपीटीआदि) का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, कार्यालयीन पत्राचार एवं नोटशीट का संचालन अनिवार्य रूप से ई आफिस के माध्यम से किया जाएगा, ताकि कागज और स्टेशनरी व्यय में कमी लाई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भौतिक प्रशिक्षण के स्थान पर आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल का उपयोग बढ़ाया जाएगा। विभागों को अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। शासन का मानना है कि इन उपायों से न केवल सरकारी खर्चों में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

दिल्ली-त्रिपुरा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस से तीन करोड़ का अवैध सोना बरामद

एजेंसी, गुवाहाटी

असम के बंगाईगांव जिले में अंतरराज्यीय तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दिल्ली-त्रिपुरा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस से करीब तीन करोड़ मूल्य के अवैध सोने की खेप बरामद की है। जीआरपी ने शनिवार को बताया कि रेलवे मार्ग से तस्करी कर भारी मात्रा में सोना ले जाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने ट्रेन में विशेष तलाशी अभियान चलाया। बंगाईगांव जिले से गुजरने के दौरान पुलिसकर्मियों ने ट्रेन के भीतर सघन जांच शुरू की।

जांच के दौरान एक यात्री की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसके सामान की तलाशी लेने पर बैग के भीतर छिपाकर रखी गई सोने की छड़ें बरामद की। गिरफ्तार आरोपित की पहचान प्रबीन सिंघा राव के रूप में हुई है। फिलहाल, उसे हिरासत में लेकर बंगाईगांव जीआरपी थाने में पूछताछ की जा रही है।

पुलिस का मानना है कि इस मामले का संबंध किसी बड़े अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से हो सकता है। बरामद सोने की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जांच जारी है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध सोना बरामद होने के बाद जांच एजेंसियां अब इस तस्करी सिंडिकेट की पूरी कड़ी खंगालने में जुट गई हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गंगटोक में किया आर्किडेरियम का दौरा

एजेंसी, गंगटोक

केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डोनर) ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को राजधानी गंगटोक के रिज पार्क में ऑर्किडेरियम का दौरा किया। स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी परिसर स्थित ऑर्किडेरियम सिक्किम की पुष्प विरासत, जैव विविधता संरक्षण और सतत पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिवसीय दौरे पर सिक्किम पर हैं। इस से पहले उन्होंने राज्य के नाम्ची जिले का दौरा किया था। राजधानी का ऑर्किडेरियम ऑर्किड की दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों की विशेषता वाला यह केंद्र राज्य की पारिस्थितिक समृद्धि और संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डालता है। ऑर्किडेरियम की यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न ऑर्किड प्रजातियों, उनकी संरक्षण प्रक्रिया और विकास क्षेत्र की संरचना का जायजा लिया। उन्होंने संस्थान की प्रशंसा की और कहा कि वह पूरा दिन ऑर्किडेरियम का निरीक्षण कर सकते हैं। सजावट का निरीक्षण करने और कांच संरक्षण प्रांगण का दौरा करने के बाद उन्होंने वीजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर करके अपनी यात्रा का समापन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गंगटोक नगर निगम के महापौर छिरिंग पाल्देन भोटिया, शहरी विकास विभाग की सचिव योगिता राई, योजना और विकास विभाग के विशेष सचिव जिग्मी बसी, जीएमसी आयुक्त गैरी चोपल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव विकास बस्नेत और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अगवानी की।

अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू होगा 'पीएमश्री' मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में लंबे इंतजार के बाद अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम श्री स्कूल स्कीम योजना लागू होने जा रही है। करीब तीन साल की देरी और विवादों के बाद राज्य में इस परियोजना की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में 15 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इस योजना को राज्य में लागू करने पर सहमति बनी। अधिकारियों के अनुसार, बहुत जल्द इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के हर ब्लॉक से कम से कम एक स्कूल का चयन किया जाएगा, जिसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर पढ़ाई के तरीके तक व्यापक बदलाव किए जाएंगे, ताकि वे आसपास के स्कूलों के लिए उदाहरण बन सकें और छात्रों के समग्र विकास में मदद कर सकें।

केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 27 हजार करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2027 तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत देशभर में हजारों स्कूलों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, पहले इस योजना को लेकर राज्य की तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और जब राज्य भी इसमें भागीदार है, तो स्कूलों के नाम के आगे 'पीएमश्री' जोड़ना उचित नहीं है। इसी कारण राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन अटका हुआ था।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई और अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रारंभिक चरण में हर जिले के हर ब्लॉक से स्कूलों का चयन किया जा रहा है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल में बदला जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार, पहले से ही कुछ केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय इस मॉडल के तहत विकसित किए जा चुके हैं। अब राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

शिक्षा जगत के कई विशेषज्ञों और संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

परीक्षा पेपर लीक,मूल्यांकन अनियमितताएं परीक्षा माफियाओं का बढ़ता नेटवर्क डंक -सीबीएसई की पारदर्शिता- 10वीं 12वीं,उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की सुविधाएं-19 मई से 22 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन -समग्र व्यापक विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» पुनर्मूल्यांकन और रीचेकिंग- 19 मई से 22 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन- सत्यापन- 26 मई से 29 मई 2026- पुनर्मूल्यांकन यानी री- इवैल्यूएशन- 26 मई से 29 मई 2026

» शिक्षा व्यवस्था केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास,आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता की आधारशिला बनी-पेपर लीक और मूल्यांकन अनियमितताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई अत्यंत आवश्यक -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया -वैश्विक स्तरपर वर्तमान डिजिटल आधुनिक और प्रौद्योगिकी आधारित युग में शिक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।कृत्रिम बुद्धिमत्ता,ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली,डिजिटल मूल्यांकन क्लाउड डेटा स्टोरेज और इंटरनेट आधारित प्रशासनिक तंत्र ने शिक्षा क्षेत्र को अत्यधिक तेज,सुविधाजनक और वैश्विक बना दिया है। आज एक छात्र मोबाइल फोन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है, ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है, डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकता है और पुनर्मूल्यांकन तक की प्रक्रिया घर बैठे पूरी कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर यही तकनीकी युग शिक्षा प्रणाली के सामने एक गंभीर संकट भी खड़ा कर रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानींगोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि परीक्षा पेपर लीक, मूल्यांकन अनियमितताएं, साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी और परीक्षा माफियाओं का बढ़ता नेटवर्क अब शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को चुनौती देने लगा है।सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अनेक नियम, कानून, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली और निगरानी तंत्र होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यह स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में परीक्षा सुरक्षा और मूल्यांकन पारदर्शिता एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।ऐसे संवेदनशील माहौल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के बाद पुनर्मूल्यांकन और रीचेकिंग की विस्तृत प्रक्रिया घोषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शनिवार, 16 मई 2026 को बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाने के लिए तीन चरणों वाली ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाएगी।इसमें सत्यापन उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन की सुविधाएं दी जाएंगी। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में छात्रों और अभिभावकों द्वारा मूल्यांकन त्रुटियों, गलत टोटलिंग, अनदेखे प्रश्नों और कम अंक दिए जाने को लेकर अनेक शिकायतें सामने आती रही हैं। डिजिटल युग में केवल परीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। साथियों बात अगर हम सीबीएसई द्वारा घोषित प्रक्रिया के चरणों की करें तो पहला महत्वपूर्ण चरण उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई फोटोकॉपी उपलब्ध कराना है। जिन छात्रों को अपने मूल्यांकन पर संदेह है, वे 19 मई से 22 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करके अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय 700 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था छात्रों को अपने उत्तरों को स्वयं देखने और मूल्यांकन प्रक्रिया को समझने का अवसर प्रदान करती है। पहले छात्रों को यह पता ही नहीं चल पाता था कि परीक्षक ने उत्तरों की जांच किस प्रकार की है, किन प्रश्नों में अंक कटे हैं और क्या कोई प्रश्न बिना जांचा रह गया है। लेकिन अब उत्तर पुस्तिका की डिजिटल कॉपी उपलब्ध होने से छात्र अपने प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर सकेंगे। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। साथियों दूसरा चरण अंकों के सत्यापन का है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र यह जांच करवा सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका के कुल अंक सही तरीके से जोड़े गए हैं या नहीं तथा कहीं कोई प्रश्न बिना जांचे तो नहीं रह गया। इसके लिए आवेदन की तिथियां 26 मई से 29 मई 2026 निर्धारित की गई हैं और शुल्क 500 रुपये प्रति विषय रखा गया है।यह प्रक्रिया इसलिए अत्यंतआवश्यक है क्योंकि कई बार मानवीय त्रुटियों के कारण अंक जोड़ने में गलती हो जाती है। भारत जैसे विशाल परीक्षा तंत्र में जहां लाखों उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, वहां छोटी-छोटी त्रुटियां भी छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। एक अंक कम या अधिक होने से कॉलेज प्रवेश, मेरिट सूची, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं की पात्रता तक प्रभावित हो सकती है। इसलिए अंक सत्यापन की सुविधा छात्रों के अधिकार और न्यायपूर्ण मूल्यांकन का सटीक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। साथियों तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण पुनर्मूल्यांकन यानी री-इवैल्यूएशन का है। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके उत्तरों का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है या अंक अपेक्षा से कम दिए गए हैं, तो वह प्रश्नवार पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए भी आवेदन अवधि 26 मई से 29 मई 2026 तक रखी गई है और प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था छात्रों को एक प्रकार का अकादमिक न्याय प्रदान करती है। कई बार परीक्षक की व्यक्तिगत व्याख्या, समय का दबाव या मानवीय

चूक छात्रों के अंकों को प्रभावित कर सकती है। पुनर्मूल्यांकन प्रणाली ऐसे मामलों में सुधार का अवसर देती है। हालांकि सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और यथावत भी रह सकते हैं। जांच के बाद जो अंक निर्धारित होंगे, वही अंतिम माने जाएंगे। यह नियम छात्रों को सावधानीपूर्वक निर्णय लेने के लिए सटीक रूप से प्रेरित करता है। साथियों सीबीएसई द्वारा सभी प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन करना भी डिजिटल शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट और परिणाम पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगेऑफलाइन आवेदन या स्कूलों के माध्यम से भेजे गए प्रपत्र अमान्य माने जाएंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी बल्कि भ्रष्टाचार और मध्यस्थता की संभावना भी कम होगी। डिजिटल प्रणाली छात्रों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा देती है और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है। हालांकि इसके साथ साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। यदि शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल बनाना है तो मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की भी आवश्यकता होगी ताकि छात्रों की जानकारी और परीक्षा डेटा सुरक्षित रह सके।सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि जो छात्र अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं या कंपार्टमेंट श्रेणी में हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए "लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स" भरने की प्रक्रिया 2 जून 2026 से शुरू होगी। यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए राहत का माध्यम है जो किसी कारणवश अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल असफल घोषित करना नहीं, बल्कि छात्रों को सुधार और पुनः अवसर प्रदान करना भी होना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया की उन्नत शिक्षा प्रणालियां निरंतर मूल्यांकन, वैकल्पिक परीक्षा और सुधारात्मक अवसरों पर जोर दे रही हैं। साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई ने पूरे देश को झकझोर दिया। सीबीआई ने कथित मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया, जो महाराष्ट्र के लातूर का एक केमिस्ट्री प्रोफेसर बताया जा रहा है। जांच एजेंसी के अनुसार वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और इसी कारण उसे प्रश्न पत्रों तक पहुंच प्राप्त थी। यह मामला केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर मौजूद विश्वास संकट का प्रतीक बन चुका है। जब परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग ही गोपनीयता भंग करने लगें, तब आम छात्रों और अभिभावकों का भरोसा स्वाभाविक रूप से डगमगाने लगता है। भारतीय समाज में सदियों से शिक्षा को ईमानदारी, परिश्रम और नैतिकता का माध्यम माना गया है, लेकिन जब "घर का भेदी लंका ढाए" जैसी स्थिति सामने आती है तो पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। यही कारण है कि अब शिक्षा मंत्रालय परीक्षा एजेंसियों और राज्य सरकारों को केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि कठोर रणनीतिक और नैतिक सुधारों की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। साथियों, दरअसल, पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा रद्द होने या छात्रों की परेशानी तक सीमित नहीं रहतीं। इनके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करते हैं, कोचिंग उद्योग अरबों रुपये का कारोबार करता है और पूरा भविष्य एक परीक्षा पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में यदि पेपर लीक हो जाए तो ईमानदार छात्रों का मनोबल टूटता है, समाज में अविश्वास बढ़ता है और योग्यता आधारित व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया के विकसित देशों में परीक्षा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया जा रहा है।अमेरिका ब्रिटेन, चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने डिजिटल एन्क्रिप्शन, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन, लाइव मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग शुरू किया है। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विशाल जनसंख्या और बहुस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के कारण चुनौतियां कहीं अधिक जटिल हैं। साथियों आज शिक्षा व्यवस्था केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता की आधारशिला बन चुकी है। यदि परीक्षा प्रणाली पर से विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रतिभा आधारित व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसलिए पेपर लीक और मूल्यांकन अनियमितताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए संगठित परीक्षा माफियाओं, तकनीकी अपराधियों और भ्रष्ट नेटवर्क पर व्यापक कार्रवाई करनी होगी। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा मंत्रालय को अब बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति अपनानी चाहिए। प्रश्न पत्र निर्माण से लेकर वितरण और मूल्यांकन तक हर चरण में डिजिटल ट्रैकिंग, एन्क्रिप्शन और निगरानी आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन तकनीक और सुरक्षित क्लाउड सर्वर जैसे उपाय भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकग्निशन और लाइव निगरानी भी लागू की जा सकती है। लेकिन तकनीक के साथ-साथ नैतिक शिक्षा और प्रशासनिक ईमानदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि व्यवस्था के भीतर मौजूद लोग ही भ्रष्ट हो जाएं तो सबसे उन्नत तकनीक भी विफल हो सकती है।इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। सीबीएसई द्वारा पुनर्मूल्यांकन और रीचेकिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है, क्योंकि इससे छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं और अंकों की जांच का अधिकार मिलता है। यह छात्र केंद्रित और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन दूसरी ओर पेपर लीक जैसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि अभी भी व्यवस्था में गहरे सुधारों की आवश्यकता है।भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। करोड़ों युवाओं का भविष्य शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय होगी तो देश की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी। लेकिन यदि पेपर लीक, अनियमितता और भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहा तो यह केवल छात्रों के सपनों को ही नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करेगा। इसलिए समय की मांग है कि शिक्षा प्रणाली को केवल तकनीकी रूप से नहीं बल्कि नैतिक और संस्थागत रूप से भी मजबूत बनाया जाए। शिक्षा मंत्रालय, परीक्षा एजेंसियों, स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सभी को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां मेहनत और योग्यता ही सफलता का आधार बने। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि, कहा जा सकता है कि वर्तमान डिजिटल युग शिक्षा के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। एक ओर तकनीक पारदर्शिता, सुविधा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मार्ग खोल रही है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध पेपर लीक और मूल्यांकन अनियमितताओं जैसी समस्याएं नई चिंताएं पैदा कर रही हैं। सीबीएसई की नई पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था इस दिशा में सकारात्मक प्रयास अवश्य है, लेकिन यह तभी सफल होगी जब पूरी परीक्षा प्रणाली में ईमानदारी, पारदर्शिता और कठोर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शिक्षा केवल परीक्षा का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आत्मा है, और इस आत्मा की रक्षा करना आज पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बन चुका है।

-संकलनकर्ता लेखक - क्र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

कैद में करुणा: पंचेन लामा और तीन दशकों का सन्नाटा

लेखिका-निमिषा सिंह

आज का मेरा यह आलेख उस बालक के नाम है जो आज 37 साल का हो चुका होगा, जो शायद आज भी किसी खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी आज़ादी का सपना देखता होगा। यह उन हज़ारों माताओं के नाम है जिनके बच्चे उनसे दूर सरकारी इमारतों में अपनी पहचान खो रहे हैं। इतिहास की क्रूरता अक्सर उन पन्नों में दर्ज होती है जहाँ सत्ता अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए मासूमियत का गला घोंट देती है। आज से ठीक इकतीस वर्ष पूर्व, जब हिमालय की चोटियों पर बर्फ पिघल रही थी, तब छह वर्षीय गेधुन चोएक्यी न्यिमा— जिन्हें 11वें पंचेन लामा के रूप में पहचाना गया था उन्हे चीनी तंत्र द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया गया। यह केवल एक बच्चे का अपहरण नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी रणनीतिक घेराबंदी थी, जिसका उद्देश्य तिब्बत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रीढ़ को तोड़ना था। व्यावहारिक रूप से समझें तो चीन के लिए पंचेन लामा का पद मात्र धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण का एक अनिवार्य उपकरण है। तिब्बती परंपरा के अनुसार, पंचेन लामा ही अगले दलाई लामा की पहचान और पुष्टि करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे में, पंचेन लामा को गायब कर और उनके स्थान पर अपनी पसंद का कठपुतली चेहरा बिठाकर,चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भविष्य के दलाई लामा की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। यह आध्यात्मिक उत्तराधिकार पर एक ऐसा राजनीतिक कब्ज़ा है, जिससे आने वाले दशकों में तिब्बत के भीतर विद्रोह के स्वर को जड़ से खत्म किया जा सके। चीन जानता है कि पंचेन लामा और दलाई लामा का रिश्ता गुरु-शिष्य का है और एक-दूसरे के पुनर्जन्म को पहचानने में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। गेडुन को गायब कर अपने कठपुतली पंचेन लामा को थोपना, तिब्बत के भविष्य और उनकी धार्मिक परंपरा को हमेशा के लिए बंधक बनाने का प्रयास है। यकीनन पंचेन लामा का गायब होना उस व्यापक अभियान का हिस्सा है जिसे सिनीसाइजेशन यानी चीनीकरण कहा जाता है। आज तिब्बत में चीन द्वारा संचालित औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल इसी दमनकारी नीति की अगली कड़ी हैं। लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से दूर कर इन सरकारी हॉस्टलों में रखना कोई सामान्य शिक्षा नीति नहीं, बल्कि उनकी भाषा, बौद्ध धर्म और पारंपरिक जड़ों को काटकर उनमें हान-चीनी पहचान भरने का एक व्यवस्थित प्रयास है। जब एक पूरी पीढ़ी अपनी जड़ों को भूल जाती है, तो सांस्कृतिक संघर्ष स्वतः ही दम तोड़ देता है। आज दुनिया मानवाधिकारों की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन पंचेन लामा का मामला संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की उस व्यावहारिक लाचारी को दर्शाता है, जहाँ चीन की आर्थिक शक्ति और वीटो की ताकत ने न्याय के तराजू को असंतुलित कर दिया है। तीन दशकों से एक व्यक्ति का अदृश्य होना और दुनिया का उसे एक ठंडा बस्ता मान लेना, आधुनिक सभ्य समाज की सबसे बड़ी नैतिक विफलता है। इस घोर अंधकार और दमन के बीच भारत एक प्रकाश स्तंभ की तरह अडिग खड़ा है, जिसने तिब्बती अस्मिता और उनकी सिसकती आस्था को अपनी ममतामयी गोद में शरण दी है। आज दुनिया भर में जो तिब्बत मुक्ति आंदोलन की गूँज सुनाई देती है, उसका केंद्र भारत की वही लोकतांत्रिक मिट्टी है जहाँ दलाई लामा जी सुरक्षित रहकर विश्व को शांति और करुणा का संदेश दे रहे हैं। भारत का यह सहयोग केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि एक रूहानी और ऐतिहासिक जुड़ाव है जिसने तिब्बत की उम्मीदों को मरने नहीं दिया। एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि पंचेन लामा का मुद्दा केवल तिब्बत का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि यह चेतना की स्वतंत्रता का वैश्विक प्रश्न है।

बीजिंग में ट्रंप की बड़ी कोशिश नाकाम?

सैयद इसरार हुसैन

अमेरिका-चीन तनाव के बीच खाली हाथ लौटे Donald Trump, दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी रहींअमेरिका और चीन के बीच लगातार बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक तनाव के बीच Donald Trump का चीन दौरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे चर्चित घटनाक्रम बन गया। चीन की राजधानी Beijing में हुई इस उच्चस्तरीय मुलाकात को दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा था। हालांकि लंबी वार्ताओं और कूटनीतिक बैठकों के बावजूद यह दौरा किसी बड़े समझौते या ठोस परिणाम के बिना समाप्त हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा केवल औपचारिक संवाद तक सीमित रही और इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच अविश्वास अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका है।

क्यों महत्वपूर्ण था यह दौरा?- पिछले कुछ वर्षों में United States और China के संबंध कई मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। व्यापार युद्ध, Taiwan विवाद, South China Sea में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, सेमीकंडक्टर तकनीक पर नियंत्रण और Artificial Intelligence की वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों के रिश्तों को लगातार प्रभावित किया है। ऐसे समय में ट्रंप की बीजिंग यात्रा को वैश्विक स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों और राजनीतिक विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों में नरमी, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संवाद को लेकर कोई सकारात्मक संकेत सामने आएगा। लेकिन वार्ता समाप्त होने के बाद जो स्थिति उभरकर सामने आई, उसने इन उम्मीदों को झटका दिया।

वार्ता में किन मुद्दों पर बनी दूरी?- सूत्रों के अनुसार, ट्रंप ने चीन से अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने, व्यापारिक असंतुलन कम करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। दूसरी ओर चीन ने अमेरिका से तकनीकी प्रतिबंधों में ढील देने तथा Taiwan मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाने की अपेक्षा जताई।

हालांकि दोनों पक्ष अपने-अपने रणनीतिक हितों पर अडिग दिखाई दिए। Xi Jinping ने स्पष्ट संकेत दिया कि चीन किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा। वहीं ट्रंप ने अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा हितों से समझौता न करने की बात दोहराई।

अंततः वार्ता बिना किसी संयुक्त घोषणा या बड़े समझौते के समाप्त हो गई, जिसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक असफल प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित असर- अमेरिका और चीन विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह टकराव आगे बढ़ता है तो इसके कई व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं—

वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि संभव है अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है छोटे और विकासशील देशों पर दोनों महाशक्तियों का रणनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे "नई Cold War" की ओर बढ़ते संकेत के रूप में भी देखा है।

भारत के लिए क्या संकेत?- India इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। एक ओर भारत के अमेरिका के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चीन उसका महत्वपूर्ण पड़ोसी और बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका-चीन तनाव और बढ़ता है, तो भारत के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों उभर सकती हैं। कई वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर वैकल्पिक निवेश केंद्र तलाश रही हैं, जिसका लाभ भारत को मिल सकता है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ी बेचैनी- ट्रंप की यह यात्रा दुनिया भर के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे "तनाव कम करने का अधूरा प्रयास" और "कूटनीतिक गतिरोध" करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक, रक्षा, साइबर सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के मुद्दों पर भी टकराव तेज़ हो सकता है।

निष्कर्ष- बीजिंग में हुई यह बहुप्रतीक्षित मुलाकात भले ही किसी ठोस समझौते तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश जरूर दे दिया कि अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों महाशक्तियां संवाद और कूटनीति के जरिए संतुलन स्थापित कर पाएंगी, या फिर वैश्विक राजनीति एक नए ध्रुवीय संघर्ष की ओर बढ़ेगी।

चांद की ओर बढ़ते कदम: भारत को स्पेस युग की जरूरत

विवेक शुक्ला

भारत आज उन चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनका समाधान पृथ्वी की सीमाओं में नहीं है। बढ़ती आबादी, सीमित संसाधन, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा की मांग हमें ब्रह्मांड की ओर देखने को मजबूर कर रही है। चंद्रमा सिर्फ एक चमकता गोला नहीं, बल्कि भविष्य का खजाना है- हेलियम-3 जैसे ईंधन, दुर्लभ खनिज, वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार और मानवता के बहु-ग्रहीय भविष्य का पहला पड़ाव। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने साबित कर दिया कि भारत अब स्पेस पावर है, लेकिन इस सफलता को स्थायी बनाने के लिए हमें युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। ठीक यही काम महेश भारती की नई किताब मून पे हनीमून कर रही है। शशि प्रकाशन से हाल ही में प्रकाशित यह पुस्तक चंद्र-अन्वेषण को रोमांचक, सुलभ और प्रेरणादायक बनाती है। महेश भारती हिंदी में लोकप्रिय विज्ञान लेखन के मजबूत हस्ताक्षर हैं। मून पे हनीमून उनके द्वारा चंद्रमा को समर्पित एक अनोखी रचना है, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भविष्य की कल्पना और भारत की उपलब्धियां एक साथ बुन दी गई हैं। शीर्षक ही किताब की भावना बयां करता है- चंद्रमा डरावना नहीं, बल्कि हनीमून जैसा रोमांचक और सपनों से भरा गंतव्य है। किताब की शुरुआत चंद्र-अन्वेषण की शुरुआत से होती है। लेखक प्राचीन काल से आधुनिक युग तक की यात्रा को इतनी जीवंत भाषा में पेश करते हैं कि पाठक खुद को उस सफर का हिस्सा महसूस करने लगता है। ग्रीक दार्शनिकों की कल्पनाएं, गैलीलियो की दूरबीन, अपोलो मिशनों का रोमांच और सोवियत लूना कार्यक्रम- सब कुछ कहानियों की शक्ल में सामने आता है। भारती जी सूखे तथ्यों की जगह भावनाओं और जिज्ञासा को जगह देते हैं, जिससे इतिहास पढ़ना मजेदार हो जाता है। अतीत की खिड़की में झांकता चांद अध्याय चंद्रमा की भू-वैज्ञानिक संरचना को सरल बनाता है। क्रेटर, लावा ट्यूब, पानी की बर्फ और चंद्रमा को पृथ्वी का 'जीवाश्म' क्यों कहा जाता है- इन सबको लेखक बोल-चाल की भाषा में समझाते हैं। कोई जटिल शब्दावली नहीं, सिर्फ स्पष्ट उदाहरण। यह अध्याय उन पाठकों के लिए खास है जो ब्रह्मांड की कहानी समझना चाहते हैं। किताब का सबसे आकर्षक हिस्सा भविष्य पर केंद्रित अध्याय हैं-

चांद पर बसेंगे और खाएंगे क्या। यहां लेखक चंद्र बस्तियों, हेबिटेट, 3D प्रिंटिंग से घर बनाने, ऑक्सीजन उत्पादन और रेगोलिथ से खेती की संभावनाओं

पर चर्चा करते हैं। खाने का मुद्दा बेहद व्यावहारिक है- हाइड्रोपोनिक्स, इन-विट्रो मीट और चंद्रमा पर उगाई जाने वाली फसलें। नासा और इसरो के वर्तमान प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए वे दिखाते हैं कि चंद्रमा पर बसना अब विज्ञान-फिक्शन नहीं, बल्कि निकट भविष्य है। ये अध्याय युवाओं में सपने जगाते हैं। सबसे गर्व का अध्याय भारत के चंद्रयान मिशन पर है। चंद्रयान-1 से चंद्रयान-3 तक की पूरी यात्रा यहां विस्तार से लेकिन रोचक ढंग से है। दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, पानी की खोज और इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत को भारती जी ने बड़े गर्व से लिखा है। यह अध्याय न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव भी जगाता है। इस किताब में पुष्परंजन और डॉ. मनीष मोहन जैसे प्रख्यात लेखकों के भी भी दो आलेख हैं। महेश भारती की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा है। हिंदी में विज्ञान लिखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इसे इतना सहज बना दिया है कि स्कूली छात्र भी आसानी से समझ सकें। हल्का ह्यूमर, जीवंत उदाहरण और पाठक को बांधे रखने वाली शैली किताब की खासियत है। मून पे हनीमून सूचना, प्रेरणा और मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण है। भारत में ऐसे विषयों पर लिखना क्यों जरूरी है? आज हमारा देश स्पेस सेक्टर को निजी भागीदारी खोल रहा है। चंद्रयान, गगनयान, आदित्य-L1 और भविष्य के मंगल मिशन हमें वैश्विक पटल पर मजबूत स्थिति दिला रहे हैं। लेकिन शिक्षा प्रणाली अभी भी रट्टा और परीक्षा पर आधारित है। विज्ञान को 'कठिन' और 'अंग्रेजी वाला' विषय मान लिया गया है। परिणामस्वरूप लाखों प्रतिभाएं स्पेस, एयरोस्पेस और टेक्नोलॉजी से दूर रह जाती हैं। हिंदी में ऐसी किताबें इस खाई को पाटती हैं। वे आम घरों तक पहुंचकर जिज्ञासा जगाती हैं, बच्चों को करियर के रूप में स्पेस साइंस चुनने के लिए प्रेरित करती हैं और राष्ट्रीय गौरव का भाव पैदा करती हैं। जब बच्चा पढ़ेगा कि भारत ने बजट की कमी के बावजूद चांद पर झंडा फहराया, तो वह खुद को सक्षम महसूस करेगा। इसके अलावा, स्पेस टेक्नोलॉजी अब विलासिता नहीं, आवश्यकता है। सैटेलाइट से कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार और भविष्य की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। जलवायु संकट के दौर में चंद्रमा जैसे संसाधन हमें नई दिशा दे सकते हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में सुलभ सामग्री ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाती है- हर वर्ग तक पहुंचाती है। महेश भारती की मून पे हनीमून सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हिंदी में लोकप्रिय विज्ञान लेखन के आंदोलन का हिस्सा है। यह युवाओं को बताती है कि चंद्रमा हमारा भविष्य है और भारत उस भविष्य का निर्माण कर सकता है। हर विज्ञान प्रेमी, छात्र, शिक्षक और अभिभावक को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज और घर-घर में इसकी जगह होनी चाहिए। दरअसल चांद, महेश भारती के दिल के बेहद करीब है। वे चांद का निरंतर अध्ययन करते हैं। उन्होंने इससे पहले 'चांद के पार चलो' शीर्षक से भी बेहद ज्ञान वर्धक किताब लिखी थी। आप कह सकते हैं कि उन्होंने चांद को सपनों में उतार दिया।

'आकाश जानता है टी20 में विकेट कैसे लेते हैं'

- संजू, ऋतुराज, उर्विल को आउट करके लखनऊ के युवा बॉलर ने खास अंदाज में मनाया जश्न

नई दिल्ली। सीएसके के खिलाफ लखनऊ के युवा गेंदबाज आकाश सिंह ने गजब की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आकाश सिंह ने पावरप्ले के दौरान 2 विकेट लिए जबकि उसके बाद उन्हें एक सफलता मिली। आकाश सिंह ने सीएसके की बैटिंग क्रम को बुरी तरह से प्रभावित किया और अपनी टीम के लिए शानदार काम किया। आकाश ने संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल को भी आउट करने में सफलता हासिल की और उन्हें आउट करने का जश्न खास अंदाज में मनाया।

संजू ऋतुराज, उर्विल को आउट करने का आकाश ने मनाया जश्न- लखनऊ के युवा बॉलर आकाश महाराज सिंह ने सीएसके के खिलाफ गजब का स्पैल डाला। उन्होंने इस मैच में अपना पहला विकेट ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लिया जिन्होंने 9 गेंदों पर 13 रन बनाए। आकाश ने ऋतुराज को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाया, लेकिन जब उन्होंने संजू सैमसन को आउट किया तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजू, ऋतुराज और उर्विल पटेल को आउट करने के बाद आकाश ने एक पर्ची निकाली और उसे हाथ में लेकर सबको दिखाया। आकाश ने तीनों बैटर को आउट करने के बाद जो पर्ची निकाली उस पर लिखा हुआ था कि आकाश ऑन फायर, आकाश जानता है कि टी20 गेम में किस तरह से विकेट लिया जाता है। इस मैच में संजू ने 20 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाए। आकाश ने इसके बाद उर्विल पटेल को आउट किया जिन्होंने 7 गेंदों पर एक चौके की मदद से 6 रन बनाए। आकाश के इन तीन विकेट ने सीएसके को इस मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। आकाश ने सभी को आउट करने के बाद पर्ची जश्न मनाया और अपनी धाक जमाई।

इटैलियन ओपन **इगा स्वियातेक को हराकर एलिना**

स्वितोलिना ने बनाई फाइनल में जगह

रोम । दो बार की चैंपियन एलिना स्वितोलिना ने रोमांचक इटैलियन ओपन 2026 के सेमीफाइनल में तीन बार की विजेता इगा स्वियातेक को 6-2, 4-6, 6-2 से हराकर तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। स्वितोलिना 2017-18 में लगातार दो ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार फाइनल मैच में पहुंची हैं। खिताबी मुकाबले में स्वितोलिना का सामना कोको गॉफ से होगा। स्वितोलिना तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम करना चाहेंगी, तो गॉफ की निगाहें पहली बार इस ट्रॉफी को उठाने पर होंगी। इसके साथ ही, दोनों खिलाड़ी सीजन का अपना पहला डब्ल्यूटीए 1000 टाइटल जीतने की कोशिश भी करेंगी। स्वितोलिना इस साल गॉफ को दो बार हरा चुकी हैं, और वह अपने इस शानदार रिकॉर्ड को फाइनल में भी कायम रखना चाहेंगी। एलिना स्वितोलिना ने स्वियातेक को 2 घंटे 14 मिनट में हराने के बाद कहा, 'इतने सालों बाद फिर से फाइनल में होना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके इस तरीके से फाइनल में पहुंचना शानदार एहसास है।'

स्वितोलिना ने सेमीफाइनल में 16 में से 11 ब्रेक पॉइंट बचाए, जिसमें फाइनल सेट में उनके सभी पांच ब्रेक पॉइंट शामिल थे। उन्होंने इस सीजन में किसी भी डब्ल्यूटीए मेन ड्रॉ में किसी भी खिलाड़ी के मुकाबले सबसे ज्यादा (59) ब्रेक पॉइंट का सामना किया है, जबकि 44 बचाए हैं। हालांकि, इसमें टीम और ग्रैंड स्लैम इवेंट शामिल नहीं हैं।

गॉफ के खिलाफ एलिना स्वितोलिना का हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-2 का रहा है। स्वितोलिना ने गॉफ को ऑस्ट्रेलियन ओपन और फिर दुबई में हराया था। डब्ल्यूटीए के अनुसार, स्वितोलिना और गॉफ की उम्र में 9 साल 182 दिन का फर्क है। यह इटैलियन ओपन के फाइनल में 1990 के बाद सबसे बड़ा उम्र का अंतर है। 1990 में मार्टिना नवरातिलोवा और मोनिका सेलेस के बीच खेले गए फाइनल में उम्र का अंतर 17 साल 45 दिन था। खास बात यह है कि गॉफ 1998-99 में वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटैलियन ओपन फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी खिलाड़ी बन गई हैं। वह 2021-22 में इगा स्वियाटेक के बाद लगातार दो रोम फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं।

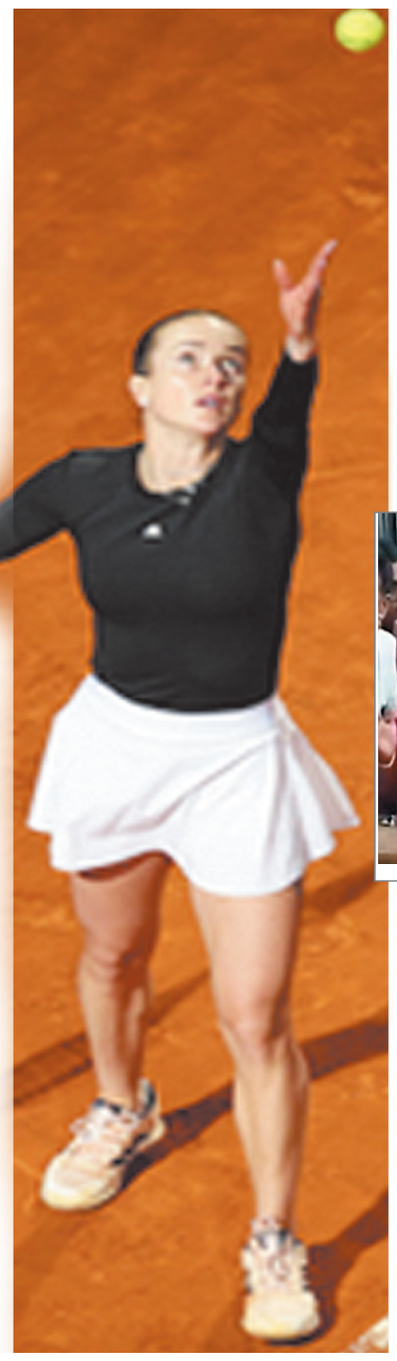

भारतीय महिला टीम ने लिया भगवान महाकाल का आशीर्वाद, भस्म आरती में शामिल हुई खिलाड़ी

उज्जैन । भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत से पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और सभी खिलाड़ी भस्म आरती में भी शामिल हुईं। भारतीय टीम की कई खिलाड़ी अपने परिवार संग आशीर्वाद लेने पहुंचीं। सभी खिलाड़ियों ने पूजा-अर्चना करते हुए टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने की मनोकामना मांगी। भारतीय टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने आईएएनएस के साथ बात करते हुए बताया कि महाकाल के दरबार में आकर उन्हें काफी शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि वह पिछले महीने भी यहां आई थीं और भस्म आरती के दौरान बाबा के दर्शन करके उन्हें काफी सुकून मिलता है। यास्तिका ने बताया कि सभी खिलाड़ी विश्व कप से पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहती थीं, ताकि टीम के लिए टूर्नामेंट शानदार गुजरे। गौरतलब है कि वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने महाकाल के दर्शन किए थे।

महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से होगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद टीम की अगली भिड़ंत 17 जून को नीदरलैंड से होगी। वहीं, 21 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर टीम इंडिया का सामना मजबूत साउथ अफ्रीका से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 25 जून को रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जबकि ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम 28 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम टी20 में भी दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। साल 2024 में खेले गए टी20 विश्व कप में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही थी।

एलएसजी की धमाकेदार जीत का मजा किरकिरा

कप्तान ऋषभ पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना

लखनऊ । लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पंत पर यह जुर्माना एलएसजी और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच हुए मुकाबले में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर लगा है। एलएसजी के गेंदबाजों ने सीएसके के खिलाफ 20 ओवर पूरे करने के लिए निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लिया। आईपीएल 2026 में यह पहला मौका है, जब एलएसजी के गेंदबाज तय समय में ओवर फेंकने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से कप्तान पंत पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल ने एक बयान में कहा, 'लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कैप्टन ऋषभ पंत पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उनकी टीम ने शुक्रवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के खिलाफ आईपीएल 2026 के 59वें मैच के दौरान धीमी गति से ओवर फेंके। यह आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत इस सीजन में उनकी टीम की पहली गलती थी, इसलिए ऋषभ पंत पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया।

अपने घरेलू मैदान पर एलएसजी का प्रदर्शन सीएसके के खिलाफ शानदार रहा। कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सीएसके ने कार्तिक शर्मा द्वारा खेली गई 42 गेंदों पर 71 रनों की दमदार पारी के बूते 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 187 रन लगाए। गेंदबाजी में एलएसजी की ओर से युवा तेज गेंदबाज आकाश महाराज ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 188 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। एलएसजी की तरफ से मिचेल मार्श ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों पर 90 रनों की आतिशी पारी खेली और मैच को पूरी तरह से एकतरफा कर दिया।

व्यापार

दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने जा रहे एलन मस्क

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क जल्दी ही ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स अगले महीने लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली यह कंपनी 2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप का टारगेट लेकर चल रही है। उसकी योजना 75 अरब डॉलर का आईपीओ लाने की है जो दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इश्यू होगा। स्पेसएक्स में मस्क की 40 से 42 फीसदी हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि कंपनी का आईपीओ आने के बाद वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। एक झटके में उनकी नेटवर्थ करीब 800 अरब डॉलर बढ़ जाएगी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स 11 जून को अपने ब्लॉकबस्टर आईपीओ की तैयारी कर रही है और उसने इसके लिए नैसडैक को लिस्टिंग वेन्यू तय किया है। कंपनी तेजी से आईपीओ की प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है और अगले बुधवार तक उसका प्रॉसपेक्टस पब्लिक हो सकता है। कंपनी 4 जून को रोडशो और 12 जून को मार्केट डेब्यू कर सकती है। पहले इसे जून के अंत में मस्क के जन्मदिवस के आसपास लिस्ट कराने की योजना थी।

रेवेन्यू और प्रॉफिट

यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ सऊदी अरामको का है जिसने 2019 में 29 अरब डॉलर जुटाए थे। स्पेसएक्स की कमाई में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की अहम हिस्सेदारी है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 16 अरब डॉलर और नेट प्रॉफिट 8 अरब डॉलर रहा था। कंपनी के बिजनेस में डायरेक्ट-टू-मोबाइल की भी काफी संभावना है। साथ ही कंपनी चांद और मंगल ग्रह के लिए स्टारशिप रॉकेट का भी विकास कर रही है। मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं।

इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले महीने लिस्टिंग की तैयारी में है इसके लिए कंपनी 2 ट्रिलियन मार्केट कैप का टारगेट लेकर चल रही है .75 अरब के साथ उसका आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा इश्यू होगा

इस आईपीओ से मस्क की नेटवर्थ करीब 800 अरब डॉलर बढ़ जाएगी मस्क की नेटवर्थ ब्लूमबर्ग बिलिनेयर के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ 680 अरब डॉलर है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 60.6 अरब डॉलर की तेजी आई है। अगर स्पेसएक्स की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचती है तो इससे मस्क की नेटवर्थ में 800 अरब डॉलर से अधिक तेजी आएगी और वह एक झटके में दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। माना जा रहा है कि स्पेसएक्स आईपीओ से जुटाई गई कुछ रकम का इस्तेमाल स्पेस-आधारित डेटा सेंटर विकसित करने में करेगी।

एमिरेट्स एनइबीडी का हो गया आरबीएल बैंक, 3 अरब डॉलर की डील को सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने आज यूएई से की। इस दौरान भारत और यूएई के बीच एनर्जी और डिफेंस समेत कई ऐतिहासिक समझौते हुए। वहीं इस दौरान दुबई स्थित दिग्गज बैंकिंग ग्रुप एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारत सरकार और सभी संबंधित नियामक निकायों से अंतिम मंजूरी मिल गई।

एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए लगभग 95.9 करोड़ शेयर खरीदेगा। यह अधिग्रहण 280 रुपये प्रति शेयर की दर से तरजीही निर्गम के माध्यम से किया जाएगा। यह कुल सौदा लगभग 3 अरब डॉलर (करीब 26,850 करोड़ रुपये) का है। करीब 3 अरब डॉलर का यह निवेश भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा इक्विटी फंड जुटाने वाला मामला है। यह पहला मौका है जब किसी विदेशी बैंकिंग संस्थान को भारत के किसी मुनाफे में चल रहे बैंक में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी गई है। ओपन ऑफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनबीडी की कुल हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। सौदे के पूरा होने पर एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल बैंक के प्रोमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आरबीएल बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक के ढांचे के तहत एक विदेशी बैंक सहायक कंपनी के रूप में काम करेगा। भविष्य में एमिरेट्स एनबीडी की मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम स्थित भारतीय शाखाओं का आरबीएल बैंक में विलय कर दिया जाएगा।

कोल इंडिया की एक और कंपनी का आएगा आईपीओ, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

नईदिल्ली, एजेंसी। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिस्टिंग और विनिवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कोयला उत्पादक कंपनी के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए शेयर बाजार में उतरने का रास्ता खुल गया है। बता दें कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को सामने रखा था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है और इसका ज्यादातर काम ओडिशा में होता है। यह लिस्टिंग केंद्र सरकार की एक और बड़ी विनिवेश पहल होगी, जिसके जरिए वह सरकारी कंपनियों में पूंजी बाजार की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है।

कोल इंडिया को मिली मंजूरी: कोल इंडिया लिमिटेड को के हिस्से के तौर पर ऑफर फॉर सेल के जरिए और बाद में अतिरिक्त चरणों में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी कम करने की अनुमति मिल गई है। इस मंजूरी से महानदी कोलफील्ड्स को के दौरान इक्विटी शेयर जारी करके और बाद में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या सेबी (सेबी) द्वारा मंजूर किए गए अन्य तरीकों से नई पूंजी जुटाने की भी अनुमति मिल गई है। सरकार ने कहा कि विनिवेश और पूंजी जुटाने की ये प्रक्रियाएं एक साथ या अलग-अलग की जा सकती हैं और ये कई चरणों में हो सकती हैं। इसके तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक कम की जा सकेगी।

कोल इंडिया की पहले भी कंपनी हुई थी लिस्टत्र आपको बता दें कि कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में से एक सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड मार्च 2026 में आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इसका आईपीओ 1,841.45 करोड़ रुपये का बुक-बिल्ट इश्यू था और यह पूरी तरह से 10.71 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल था। यह पब्लिक इश्यू 172 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसके शेयर अभी हस्श्व पर 232.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। इस बीच, कोल इंडिया के शेयर 462.20 रुपये पर बंद हुए, जो गुरुवार की क्लोजिंग कीमत से 8.15 रुपये या 1.79 प्रतिशत अधिक थे। कोल इंडिया की बात करें तो देश के घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। कंपनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में उसका उत्पादन 1.7 प्रतिशत घटकर 76.81 करोड़ टन रहा जो 2024-25 में 78.11 करोड़ टन था। वहीं, मार्च महीने में उत्पादन 8.58 करोड़ टन से घटकर 8.45 करोड़ टन रह गया। ऑटोमोटिव लाइटिंग बनाने वाली कंपनी नियोलाइट लाइटिंग्स, शराब इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर एस्प्री स्पिरिट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन के प्रस्तावित पब्लिक ऑफरिंग को मंजूरी दे दी है। इससे इन कंपनियों के लिए प्राइमरी मार्केट में उतरने का रास्ता खुल गया है। इन तीनों में से, नियोलाइट लाइटिंग्स ने नए इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल के कॉम्बिनेशन के जरिए 600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। एस्प्री स्पिरिट्स के प्रस्तावित में 140 करोड़ रुपये तक का एक नया इश्यू शामिल है।

60 लाख की नौकरी छोड़ वाट्सएप से शुरू किया काम, आज खड़ी कर दी 12 करोड़ की कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी। आज के डिजिटल युग में सफलता के लिए बड़े शोरूम की नहीं, बल्कि एक ठोस विजन और सही शुरुआत की जरूरत है। इसकी जीती-जागती मिसाल हैं राम्या देवनाथन। 18 साल तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी दिग्गज कंपनी में डिलीवरी मैनेजर के तौर पर काम करने वाली राम्या ने जब अपना 60 लाख रुपये का सालाना पैकेज छोड़ा, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह साड़ियों के कारोबार में क्रांति ला देंगी।

कोविड के दौर में जब दुनिया थम सी गई थी, राम्या ने अपनी नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया। साल 2021 में उन्होंने अपनी रिश्तेदार विबिशिका कार्की के साथ मिलकर महज 2 लाख रुपये के निवेश से मद्रास साड़ी की नींव रखी। इस सफर की शुरुआत किसी भव्य ऑफिस से नहीं, बल्कि चेन्नई में उनके घर के पास स्थित 10×10 फीट के एक छोटे से कमरे से हुई। शुरू में टीम में सिर्फ चार लोग थे, जिनमें दो लड़कियां उनकी मदद के लिए थीं। उनका यह काम कुछ ही वर्षों में 12 करोड़ रुपये के कारोबार में बदल गया है। राम्या ने बिजनेस में सोशल मीडिया की ताकत समझी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)